▶▶ कृषि ▶▶ समीक्षा ▶▶ मुद्दा

कुल पृष्ठ: 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

पौष–माघ 2075, जनवरी 2019

आर.सी.ई.पी एवं भारत

स्वदेशी पत्रिका और स्वदेशी परिवार की ओर से
स्वदेशी के सभी पाठकों, लेखकों तथा स्वदेशी में योगदानकर्त्ता को

गणतंत्र दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएं

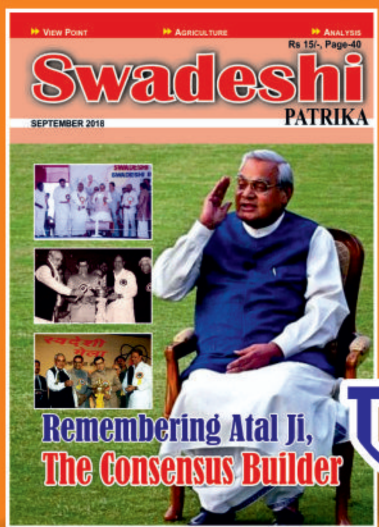

VOICE OF

SELF RELIANT INDIA

SWADESHI
Patrika

स्वदेशी
पत्रिका

पढ़ें और पढ़ायें

स्वदेशी पत्रिका

अ नु क्र म

वर्ष–27, अंक–1

पौष–माघ 2075 जनवरी 2019

संपादक

अजेय भारती

सह–संपादक

अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन

सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4

समाचार परिक्रमा 33-37

तृतीय मुख्य पृष्ठ 39

चतुर्थ मुख्य पृष्ठ 40

आवरण कथा – पृष्ठ–6

मुक्त व्यापार समझौते और भारत

अफसर जाफरी

1 मुख्य पृष्ठ

2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

12 सीमापार
आर्थिक संकट में पाकिस्तान
.... डॉ. अश्वनी महाजन

14 आकलन
मोदी मंत्रः साफ नीयत, सही विकास
.... अनिल तिवारी

18 खेतीबारी
किसानों को कीमत नहीं, आय चाहिए
.... देविन्दर शर्मा

20 कृषि
किसान की समस्या पर नई सोच की जरूरत
.... डॉ. भरत झुनझुनवाला

22 समीक्षा
विकास के लिए सुदृढ़ वित्तीय आधारभूत संरचना आवश्यक
.... डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

24 मुद्दा
जनता के लिए आर्थिक सुधारों की जरूरत
.... शिवाजी सरकार

26 ऊर्जा
सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम
.... स्वदेशी संवाद

29 तकनीक
भारत में एआई नवाचार में रोजगार की संभावनाएं (भाग–1)
.... डॉ. रेखा भट्ट

32 पुस्तक समीक्षा
बहुसंस्कृतिवाद व आतंकवाद
.... वैदेही तिवारी

38 स्वदेशी गतिविधियां
डॉ.अश्वनी महाजन 'स्कॉच चैलेंजर अवार्ड' से सम्मानित

पाठकनामा

कर्जखोर न बना दे कर्जमाफी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी किसानों का कर्ज माफ करने की वकालत करते हैं। ऐसा कर वे देश भर के किसानों को कर्जखोर बना रहे हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का नुकसान करने का यह घृणित प्रयास है। हो सकता है कि वे आगे कार लोन, हाउसिंग लोन, आटो लोन, एजुकेशन लोन आदि को माफ करने की बात कहे। क्योंकि वे सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस देश की कुल जनसंख्या सवा सौ करोड़ है। इनमें सिर्फ सात करोड़ लोग कर–दाता हैं। इसी से सरकार चलती है।

कर्जमाफी से पहले इनकी भावनाओं का भी स्मरण रखना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए नागरिकों से गैस की सब्सिडी छोड़ने और रेलयात्रा करने वाले बुजुर्गों से टिकट में मिलने वाली छूट का त्याग करने का आग्रह करते है। लाखों लोगों ने देशहित में उनकी अपील पर सुविधाओं का त्याग भी किया है। दूसरी ओर राहुल गांधी देश को आर्थिक संकट में डालने का कुत्सित प्रयास कर रहे है। इस विषय को चुनाव आयोग को भी संज्ञान में लेना चाहिए। क्योंकि कर्जमाफी एक प्रकार की रिश्वत है। अगर कांग्रेस की कर्जमाफी की इच्छा है तो वह सरकारी खजाने से क्यों? कांग्रेस के विधायक, सांसद, पार्षद, पदाधिकारी जो सब मालदार है, अपने फंड से किसानों का सहयोग कर सकते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के अधिकांश नेता राजपरिवार से है। वे पीढ़ी दर पीढ़ी किसानों का शोषण करते रहे है। वे किसानों के सहयोग का खाता खोल सकते हैं। इस कार्य से उनका वोट बैंक भी बढ़ेगा।

अब कर्जमाफी के कारण गांवों में दलालों का एक ऐसा तबका विकसित हो रहा है जो लोन दिलाने और फिर उसे माफ कराने का धंधा कर मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे रहा है और अपनी चांदी काट रहा है। राहुल गांधी देश के सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष है। अब तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि कर्जमाफी की नीति एक तरह से आत्मघाती नीति है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर बीज, खाद्य, उर्वरक, सिंचाई, अन्न भंडारण आदि में सुधार करें, किसानों को भीखमंगा नहीं बनाएं।

उमेश प्रसाद सिंह, *लक्ष्मी नगर, दिल्ली*

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com
अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

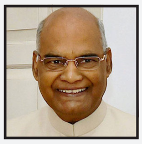

मुद्रा योजना और सूक्ष्म, मध्यम तथा छोटे उद्यमों के लिए आउटरीच जैसे अभिनव प्रयोग ऐसे कार्यक्रमों के उदाहरण हैं जिसने लाखों व्यक्तियों को सक्षम किया है। इन कार्यक्रमों से नौकरी चाहने वालों को नौकरी सजक बनने में मदद मिली है।

रामनाथ कोविंद
राष्ट्रपति, भारत

बापू की 150वीं और नेल्सन मंडेला की 100वीं जयंती पर हम उनके आदर्शों को याद करते हैं और न्यायपूर्ण और दयालु समाज बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत

"पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत भारत ने वास्तव में कुछ मूलभूत सुधार किए हैं। इनमें गुड्स एंड सर्विसस टैक्स (जीएसटी), दिवाला और दिवालियापन संहिता... वित्तीय समावेशन पर उन्होंने जो कुछ किया है वह वास्तव में महत्वपूर्ण है"

मौरिस ओब्सटफेल्ड
आई.एम.एफ. प्रमुख

मजबूत भारत का रास्ता आम आदमी के संकल्पों से होकर जाता है। निहित स्वार्थो से जुड़े नेता जो खुद को देश से ऊपर समझते है उन्हें अपना रास्ता चुनना होगा।

सरोज मित्र
राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

तेल कीमतों के बढ़ने और रूपये के गिरने के आसार नहीं

पिछले कुछ माह में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगातार बढ़ती तेल कीमतों के चलते भारतीय रूपया संकट में आ गया था और मात्र कुछ ही महीनों में यह 13 प्रतिशत गिरावट के साथ अक्टूबर 2018 में 74.5 रूपए प्रति डालर तक पहुंच गया था। यही नहीं उस कालखंड में विदेशी निवेशकों ने भी शेयर बाजारों समेत भारत के प्रतिभूति बाजारों में भारी बिकवाली करते हुए देश से बहुत अधिक विदेशी मुद्रा विदेशों को स्थानांतरित कर दी थी, जिसके कारण रूपए पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में रूपए के गिरते मूल्य में आग में घी डालने का काम करते हुए सरकारी तंत्र के लोगों द्वारा ऐसे बयान दिए गए कि भारतीय रूपए का मूल्य अभी भी ज्यादा है और इसमें और अधिक गिरावट हो सकती है। भारत सरकार के आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष गर्ग ने यह तक कहा कि रूपया 80 रूपए प्रति डालर तक जा सकता है और उसका वही स्तर सही होगा। लगभग इसी प्रकार के बयान तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविन्द सुब्रमण्यम और नीति आयोग की ओर से भी आते रहे। नरेन्द्र मोदी सरकार के पहले चार वर्षो में रूपए का मूल्य काफी हद तक सुधार गया था और जो रूपया अगस्त 2013 में अमरीकी डालर के मुकाबले 68.84 रूपए प्रति डालर तक पहुंच चुका था, वह बाद में सुधारकर 62 रूपए के प्रति डालर के आसपास पहुंच गया।

बढ़ती तेल कीमतों और निवेश के बर्हिगमन के कारण रूपया कमजोर तो हुआ लेकिन यह कमजोरी एक अल्पकालिक कमजोरी थी, तेल की कीमतों में कमी के साथ ही रूपया फिर से मजबूत होने लगा और विदेशी निवेशक भी वापिस आ गए और रूपया सुधरकर 11 जनवरी 2019 तक 70.42 रूपए प्रति डालर तक पहुंच गया। ऐसे में उन सभी अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माण से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण लोगों के अनुमान गलत सिद्ध हो गए जो रूपए को 80 से 85 रूपए प्रति डालर तक पहुंचाने की भविष्यवाणियां कर रहे थे। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों के बढ़ने का प्रमुख कारण 'ओपेक' देशों का कार्टेल रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में 'ओपेक' कमजोर हुआ है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अमरीका ने अपना कच्चे तेल का उत्पादन काफी हद तक बढ़ा दिया है। ऐसे में साऊदी अरब, जो 'ओपेक' का नेतृत्व कर रहा था, भी अपने उत्पादन को घटाने में झिझकने लगा और अमरीका द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन बढ़ाने के बाद उसने उत्पादन को घटाकर तेल की कीमतों को बढ़ाने का अपना इरादा त्याग दिया और लम्बे समय तक तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटते हुए 2017 में 42.5 डालर प्रति बैरल तक पहुंच गई। इसके बाद ओपेक देशों ने फिर से सिर उठाना शुरू किया और एक बार फिर ओपेक देशों ने उत्पादन घटाकर कीमतों को बढ़ाना शुरू कर दिया। भारत तेल का एक बड़ा आयातक देश है, उसके बावजूद उसने तेल की बाजार कीमत को हमेशा सिर झुकाकर ही स्वीकार किया। लेकिन इस बार जब 'ओपेक' की कार्यवाही के चलते कीमतें बढ़ी तो भारतीय प्रधानमंत्री ने 'ओपेक' देशों के भारत में संपन्न सम्मेलन में बड़े सख्त शब्दों में चेतावनी दी है कि भारत इसे इस प्रकार स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए 'ओपेक' देशों को अनुशासन में रहना होगा। उधर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी उथल–पुथल होने लगा और अमरीका ने कुछ तेल निर्यातक देशों जैसे ईरान और वेनेजुएला पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इस अनिश्चिता के चलते भी तेल की कीमतों में वृद्धि होती गई, जो अन्य बातों के अतिरिक्त भारत के विदेशी भुगतान के लिए मुश्किल का सबब बनी। लेकिन भारत समेत कई मुल्कों ने तेल निर्यातक देशों के खिलाफ प्रतिबंधों को न मानने की चेतावनी दी और अमरीका ने भी अपने पूर्व के आग्रह को छोड़ते हुए इन देशों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों के संबंध में भारत समेत कई अन्य देशों को छूट दे दी। दूसरी ओर कतर, जो ओपेक का महत्वपूर्ण सदस्य रहा है, ने भी ओपेक से अलग होने के निर्णय की घोषणा कर दी। ओपेक देशों के एकाधिकार को अब एक भारी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अमरीकी शैल (कच्चे तेल की कंपनी) उत्पादन में भारी वृद्धि के सामने अब ओपेक देश स्वयं को बौना महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2018 वर्ष के अंत तक कच्चे तेल की कीमत 42 डालर प्रति बैरल तक पहुंच गई है।

अर्थशास्त्री और अन्य लोग जो यह कहते हैं कि भारतीय रूपए का मूल्य ज्यादा है और उसमें गिरावट आनी चाहिए, यह तर्क देते हैं कि 'वास्तविक प्रभावी विनिमय दर' यानि 'रियल इफैक्टिव एक्सचेंज रेट' (रियर) के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रूपए का मूल्य ज्यादा है। गौरतलब है कि 'रियर' एक देश की अन्य प्रमुख करेंसियों के सूचकांक (महंगाई दर को समायोजित करते हुए) के संबंध के रूप में दर्शाया जाता है। लेकिन विनिमय दर के बारे में किसी एक आंकड़े पर आधारित रखकर फैसला नहीं लिया जा सकता, खासतौर पर तब जब अन्य मानक उससे भिन्न है।

विनिमय दर निर्धारण के लिए कई मानक होते हैं। एक मानक है क्रय शक्ति समता यानि 'पर्चेजिंग पावर पेरिटी'। कई अर्थशास्त्रियों को मानना है कि विनिमय दर निर्धारण में क्रय शक्ति क्षमता के आंकड़ों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय रूपया हो या कोई अन्य करेंसी, उसकी वास्तविक मजबूती बाजार विनिमय दर से नहीं बल्कि उसके अपने देश में क्रय शक्ति पर आधारित होती है। भारतीय रूपये की क्रय शक्ति क्षमता विनिमय दर से 3.3 गुना ज्यादा है। जबकि अन्य देशों को यदि देखें तो चीन की क्रय शक्ति क्षमता विनिमय दर से 2.05 गुणा ही ज्यादा है। ब्राजील में यह 1.3 गुणा ज्यादा है, दक्षिण अफ्रीका में यह 1.63 गुणा ज्यादा है, जबकि रूस में यह 2.16 गुणा ही ज्यादा है। यानि कहा जा सकता है कि भारत में विनिमय दर की तुलना में रूपये की क्रय क्षमता 'ब्रिक्स' देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है। दूसरी और दुनिया में प्रमुखता से माना जाने वाला एक अन्य मानक है, 'बिग मैक इंडेक्स'। यह दुनिया में मैकडोनाल्ड के बर्गर की कीमत से आकलित किया जाता है। इसके अनुसार भी भारतीय रूपये की बर्गर की क्रय क्षमता ज्यादा है। शायद यही कारण है कि भारतीय रूपये की विनिमय दर कभी भी 'रियर' पर आधारित नहीं रही। देखना होगा कि क्रय शक्ति क्षमता और 'बिग मैक इंडेक्स' के आधार पर रूपये में सुधार कब और कैसे हो सकता है, इसके लिए हमें उत्पादन बढ़ाते हुए आयात कम कर विदेशी व्यापार को संतुलित करना होगा।

आवरण कथा

मुक्त व्यापार समझौते और भारत

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक देश या व्यापारिक गुट आपस में आयात और निर्यात सहज बनाने के लिए सीमा शुल्क में कटौती या कमी एवं गैर–सीमा शुल्क संबंधी अवरोधों को दूर करने के लिए सहमत होते हैं। किसी भी देश के व्यापार में आयात और निर्यात का संतुलन होना चाहिए। अगर किसी देश का आयात, निर्यात के मुकाबले ज्यादा होने लगे तो उसे व्यापार घाटा (ट्रेड डिफिसिट) कहा जाता है। इसी तरह अगर निर्यात देश के आयात से ज्यादा हो तो उसे व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) कहेंगे। नीति आयोग द्वारा तैयार 'मुक्त व्यापार समझौते और उनकी कीमतों पर रिपोर्ट' के अनुसार आसियान, दक्षिण कोरिया, और जापान के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के बाद से भारत को अधिक व्यापार घाटा (ट्रेड डिफिसिट) का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत का अन्य देशों की तुलना में सीमा शुल्क ज्यादा था जिसके कारण भारत को सीमा शुल्क में ज्यादा कटौती करनी पड़ी। मुक्त व्यापार समझौतों में आमतौर पर देशों के बीच व्यापार प्रतिबंधों को हटाया या कम किया जाता है जिससे माल और सेवाओं की आवाजाही को सुगम बनाया जा सके। हालांकि, विश्व व्यापार संगठन (WTO) के विपरीत, इन मुक्त व्यापार समझौतों में सीमा शुल्क में कटौती को बेस रेट (आधार दर)[1] के संदर्भ में किया जाता है। अर्थात् जिस दर पर सबसे पसंदीदा देशों (मोस्ट फेवर्ड नेशन) के लिए शुल्क तय की गई हो। विश्व व्यापार संगठन में यह कटौती हमेशा 'बाध्यकारी दर'[2] (Bound Rate) पर आधारित होती है, न कि पसंदीदा देशों पर लागू दरों (MFN Applied Rate) के आधार पर।

यहां यह महत्वपूर्ण होता है कि समझौते में शामिल देशों के पास सौदेबाजी की कितनी शक्ति है। इसी आधार पर यह तय होता है कि मुक्त व्यापार समझौतो में किस हद तक व्यापार, सेवाओं और निवेश को उदार बनाया जाएगा। विश्व व्यापार संगठन के समझौतों में ऐसा नहीं होता है। मुक्त व्यापार समझौते दरअसल एक और तरीका है जिससे सरकारों

मुक्त व्यापार समझौतों में आमतौर पर देशों के बीच व्यापार प्रतिबंधों को हटाया या कम किया जाता है जिससे माल और सेवाओं की आवाजाही को सुगम बनाया जा सके।

– अफसर जाफरी

को कॉरपोरेट–भूमंडलीकरण–एजेंडे पर आधारित उदारीकरण, निजीकरण और विनियमन की ओर ढ़केला जाता है।

पारंपरिक रूप से उत्तर–दक्षिण (North South) मुक्त व्यापार समझौते बेहद व्यापक होते हैं। इनकी मंशा ट्रांस्नैशनल कॉरपोरेट्स के लिए नए अवसर खोलने का होता है जिससे वे विकासशील देशों से और ज्यादा मुनाफा नीचोड़ सकें। दरअसल, ये उत्तर–दक्षिण समझौते नव–औपनिवेशिक होते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे के लिए विकासशील देशों की प्राकृतिक संसाधान और सस्ते मजदूरों को उपलब्ध कराया जाता है। दूसरी तरफ, दक्षिण–दक्षिण (South-South) समझौते (जैसे भारत और श्रीलंका के बीच) आमतौर पर, कम विस्तृत होते हैं। इनका रुख राष्ट्रीय कानून में बड़े बदलाव लाने का नहीं होता है। इसके बावजूद भी किसानों, मजदूरों और पर्यावरण के ऊपर इसके भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। हाल के वर्षों में, दक्षिणी देशों या विकासशील देशों के बीच समझौतों का स्वरूप भी विकसित (उत्तर) और विकासशील (दक्षिण) देशों के बीच के समझौतों की तरह हो गया है। क्योंकि माल (कृषि या औद्योगिक उत्पाद) या सेवाओं में व्यापार (बैंकिंग, निर्माण, व्यापार, शिक्षा और अन्य सेवाएं इत्यादि) के अलावा आज के अधिकांश मुक्त व्यापार समझौतों में 'बौद्धिक संपदा अधिकार' (आई.पी.आर), निवेश, वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global Value Chain), सरकारी खरीद और प्रतिस्पर्धा नीतियां इत्यादि शामिल हैं। इस प्रकार देखा जाए तो आज के अधिकांश मुक्त व्यापार समझौते विश्व व्यापार संगठन से भी कहीं आगे निकल चुके हैं। ये समझौते अपने सदस्य देशों के ऊपर कानूनन बाध्यकारी कर्तव्यों की बात करते हैं। इससे इन देशों की नीति निर्धारण स्वतंत्रता बाधित होती है। आजीविका, दवाइयों और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, जनसेवा, और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कृषि क्षेत्र में इन मुक्त व्यापार समझौतों के कारण आयात शुल्क में भारी कटौती की गई है, कृषि प्रसंस्करण और खुदरा व्यापार को बढ़ावा मिला है और सख्त आई.पी. आर. प्रावधानों के कारण छोटे एवं सीमांत किसानों के उपर बुरा प्रभाव पड़ा है। बीज उत्पादन, बीज संरक्षण और बीज बेचने के उनके अधिकार छिन रहे हैं।

मुक्त व्यापार समझौतों के कई प्रकार होते हैं– द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, या बहुपक्षीय। भारत ने हर प्रकार के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। कुछ द्विपक्षीय व्यापार समझौते निवेश के क्षेत्र में भी होते हैं जिन्हें द्विपक्षीय निवेश संधि (बाइलेटेरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ – BIT) कहा जाता है।

कृषि क्षेत्र में इन मुक्त व्यापार समझौतों के कारण आयात शुल्क में भारी कटौती की गई है, कृषि प्रसंस्करण और खुदरा व्यापार को बढ़ावा मिला है और सख्त आई.पी.आर. प्रावधानों के कारण छोटे एवं सीमांत किसानों के उपर बुरा प्रभाव पड़ा है।

पिछले कुछ वर्षों में एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत हुई है जिसमें मुक्त व्यापार समझौते में शामिल सदस्य देश – (1) दो या दो से अधिक होते हैं; (2) जो जरूरी नहीं है कि एक ही क्षेत्र या महाद्वीप से हों; और (3) ऐसे विषयों पर हों जिनका दायरा डब्ल्यूटीओ के दायरे से भी आगे हो। उदाहरण के रूप में भारत इस वक्त एक बहुपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता में शामिल है जिसे 'क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक साझेदारी' या 'रीज़नल कंप्रिहेंसिव इकोनामिक पार्टनरशिप' (आर.सी.ई.पी.) कहा जा रहा है। इस वार्ता में भारत के साथ करीब 15 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें से 10 सदस्य (ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और फिलीपींस) आसियान से हैं और बाकी के देश – ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया हैं। इस बहुपक्षीय व्यापार समझौते को नए दौर के मेगा मुक्त व्यापार समझौतों (Mega FTA) के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि यह न केवल अपने आकार में बड़े हैं बल्कि भौगोलिक दृष्टि से विविध भी है। इसके साथ–साथ इस समझौते में एसे महत्वाकांक्षी मुद्दे भी शामिल हैं जिन्हें अक्सर 'डब्ल्यूटीओ–प्लस' मुद्दों के रूप में जाना जाता है।

अगर यह आरसीईपी समझौता तैयार हो जाता है तो यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापार गुट बन जाएगा। इसकी परिधि में विश्व की 45 प्रतिशत जनसंख्या, 30 प्रतिशत वैश्विक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी), 27.4 प्रतिशत वैश्विक माल व्यापार, और 23 प्रतिशत वैश्विक सेवा व्यापार शामिल होगा। आरसीईपी समझौते में यह सभी विषय शामिल होंगे, जैसे माल, सेवाएं, निवेश, आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग, बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्धा और विवाद निपटान, इत्यादि। नये मुद्दों को भी जोड़ा जा सकता है।

16 देशों के बीच आरसीईपी समझौता वार्ता पूरी रफ्तार से चल रही है। सितंबर 2018 तक इस वार्ता के 23 दौर पूरे हो चुके हैं, जिसमें से 6 बार मंत्रीस्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। पिछली बैठक मुख्य–वार्ताकारों के स्तर पर अक्टूबर 2018 में ऑकलैंड में हुई। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष दिसंबर तक आरसीईपी समझौता वार्ता

मुक्त व्यापार समझौतों के बुरे प्रभाव अभी से औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में दिख रहे हैं।

अपने अंतिम चरण तक पहुंच जाएगी। परंतु भारत के व्यापार मंत्री के बयान के अनुसार इस वर्ष के अंत तक यह पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि शुल्क कटौती के ऊपर बातचीत अभी भी अधूरी है और सदस्य देशों के बीच अभी भी सेवा, निवेश तथा अन्य मुद्दों पर व्यापार के ऊपर सहमति नहीं बनी है।

मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों का असर

मुक्त व्यापार समझौतों के बुरे प्रभाव अभी से औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में दिख रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत के औद्योगिक समूह लगातार मुक्त व्यापार समझौतों से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं – विशेष रूप से भारत बनाम – श्रीलंका (1998), थाईलैंड (2003), सिंगापुर (2005), दक्षिण कोरिया (2009), आसियान (2009), जापान (2011) और मलेशिया (2011) समझौतों के संदर्भ में। इनमें से अधिकतर समझौतों के कारण भारत को अपना सीमा–शुल्क कम करना पड़ा जिससे निर्यात गिर गया और आयात कहीं अधिक रफ्तार से बढ़ने लगा। जापान के साथ भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2010–11 में 3.6 बिलियन डॉलर[3] था। परंतु भारत–जापान मुक्त व्यापार समझौते के बाद 2012–13 में यह व्यापार घाटा बढ़कर करीब–करीब दोगुना हो गया (6.3 बिलियन डॉलर)। इसी तरह, वर्ष 2007–08 से लेकर 2009–10 के बीच भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आयात 7.8 बिलियन डॉलर था, जो मुक्त व्यापार समझौते के बाद वर्ष 2010–11 से 2012–13 के बीच बढ़कर 12.1 बिलियन डॉलर हो गया। इस अवधि के दौरान भारत और दक्षिण कोरिया के बीच निर्यात में केवल मामूली बढ़ोतरी हुई। यह 3.4 बिलियन डॉलर से बढ़कर केवल 4.1 बिलियन डॉलर तक ही पहुंचा, परंतु दूसरी तरफ व्यापार घाटा 4.4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 8 बिलियन डॉलर हो गया। आरसीईपी भारत का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता होने वाला है, इसकी प्रतिबद्धताएं पिछले समझौतों से कहीं ज्यादा बड़ी और गंभीर होने वाली हैं।

भारत का सबसे बड़ा एवं पुराना शीर्ष व्यापार निकाय–'फिक्की' (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज या FICCI) ने भी इन्हीं वजहों से किसी भी नए मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने पर रोक लगाने की मांग की है। अगस्त 2013 में फिक्की ने 12 सूत्रीय 'विनिर्माण जनादेश' के माध्यम से यह कहा कि ''इन समझौते में ऐसा माना जाता है कि परस्पर लाभकारी परिणाम का प्रावधान होंगे, पर अभी तक के अनुभव कुछ और ही बताते हैं, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में। इसलिए सारे मौजूदा समझौतों की समीक्षा होनी चाहिए और जब तक यह मूल्यांकन पुरा न हो सरकार को तुरंत नए समझौते पर रोक लगा देनी चाहिए।''

कृषि क्षेत्र में भी मुक्त व्यापार समझौतों के काफी बुरे परिणाम दिख रहे हैं क्योंकि यहां न केवल सीमा–शुल्क को कम किया गया है (जैसा कि डब्ल्यूटीओ के मामले में होता है) बल्कि अधिकतर जगहों पर पूरी तरह से खत्म ही कर दिया गया है। भारत – श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद श्रीलंका से सस्ती काली मिर्च और इलायची का आयात होने लगा है जिसका केरल के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। वर्ष 2015 में श्रीलंका से काली मिर्च की सस्ती किस्म का आयात 9,500–9,750 डॉलर प्रति टन पर हो रहा था। उस वक्त भारत में इसकी कीमत 11,400 डॉलर प्रति टन थी। भारत के काली मिर्च किसानों के ऊपर एक और बड़ा आघात तब पड़ा जब भारत–आसियान मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। अब ज्यादातर काली मिर्च का आयात वियतनाम (जो विश्व का सबसे बड़ा काली मिर्च निर्यातक है) और इंडोनेशिया से होने लगा। वर्ष 2015 में वियतनाम ने 9,800 डॉलर प्रति टन और इंडोनेशिया ने 9,747 डॉलर प्रति टन पर काली मिर्च का निर्यात किया, जो भारतीय कीमत से कहीं कम थी। भारत में काली मिर्च के अत्यधिक आयात से घरेलू कीमत पर बहुत बुरा असर पड़ा। वर्ष 2011–12 में काली मिर्च की स्थानीय कीमत थी 240 रुपये प्रति किलो थी पर जनवरी 2016 में यह घटकर मात्र 80 रुपये प्रति किलो हो गई।

काली मिर्च किसानों के अलावा आसियान देशों के साथ समझौता का भारत के रबर उत्पादकों के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ा। वियतनाम और इंडोनेशिया से होने वाले सस्ते रबर आयात के कारण अभी तक 10 लाख से भी ज्यादा रबर किसानों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। वर्ष 2013 तक भारत रबर उत्पादन में

आत्मनिर्भर था पर अब यह आयात के ऊपर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होता जा रहा है। वर्ष 2013 से 2015 के बीच रबर का आयात करीब–करीब दोगुना बढ़ गया। वर्ष 2013 में यह 2.6 लाख मैट्रिक टन था जो 2015 के अंत तक पहुंचते–पहुंचते 4.4 लाख मैट्रिक टन हो गया। रबर का निर्यात अब अपने निचले स्तर पर पहुंच चुका है। 2015 में भारत ने मात्र 1002 टन रबर का निर्यात किया, जबकि वर्ष 2013 में 30,549 टन का निर्यात हुआ था। रबर की कीमत 207 रुपये प्रति किलो से घटकर 132.6 रुपए प्रति किलो हो गई है।

भारत–आसियान मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर के बाद दक्षिण भारत के नारियल किसानों को भी अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ रहा है। नारियल के दाम घटकर मात्र 3 रुपये प्रति इकाई हो गया था। नारियल की कीमतों में गिरावट के पीछे प्रमुख कारण फिलिपींस और इंडोनेशिया से होने वाला सस्ते नारियल के आयात है।

भारतीय उद्योग और कृषि के ऊपर इतने गंभीर प्रभाव पड़ने के बावजूद भारतीय सरकार के उत्साह में कोई कमी नहीं है। इस वक्त करीब 18 अन्य मुक्त व्यापार समझौता वार्ताओं में सरकार शामिल है। ये वार्ताएं यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपीय संघ, इजरायल, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, अफ्रीकी महाद्वीप मुक्त व्यापार समझौता, उरूग्वे, मर्कोसुर और वेनेजुएला के साथ चल रही हैं।

दूसरी तरफ इन वार्ताओं की प्रक्रिया भी काफी समस्यात्मक, गैर–लोकतांत्रिक और संदिग्ध रूप से गोपनीय होती है। समझौतों के दौरान आम जनता एवं उनके संसदीय प्रतिनिधियों को इससे जुड़े किसी भी दस्तावेज को देखने का अधिकार नहीं है। शायद इसीलिए आज तक किसी भी द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का कभी भी किसी राज्य सरकार, राजनीतिक पार्टी या सामाजिक आंदोलनों की तरफ से प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। केवल भारत–आसियान मुक्त व्यापार समझौतों का राजनीतिक विरोध (वाम लोकतांत्रिक फ्रंट केरल सरकार द्वारा) हुआ। केरल सहित दक्षिण भारत के किसानों और मछुआरे समूहों ने भी इसका प्रतिरोध किया। भारत में इन समझौतों का राष्ट्रीय संसद द्वारा अनुसमर्थन की कोई प्रक्रिया नहीं है। करीब–करीब सभी मुक्त व्यापार समझौतों में राज्य सरकारों के साथ भी कोई परामर्श नहीं किया गया, भले ही वह कृषि जैसे विषयों पर ही क्यों न हो जो राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आते हैं।

भारतीय उद्योग और कृषि के ऊपर इतने गंभीर प्रभाव पड़ने के बावजूद भारतीय सरकार के उत्साह में कोई कमी नहीं है।

आरसीईपी से जुड़ी प्रमुख चिंताएं

किसी भी अन्य मुक्त व्यापार समझौते की ही तरह आरसीईपी समझौता वार्ता में भी कोई पारदर्शिता नहीं रखी गई है। प्रभावित हाने वाली जनता या क्षेत्रीय समूहों, जैसे किसान, महिला, मजदूर, स्वास्थ्य समूहों इत्यादि को कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। न ही कभी उनसे कोई परामर्श किया गया है। आरसीईपी में अनेकों विषय शामिल हैं पर फिर भी बिना किसी सार्वजनिक प्रकटीकरण के अभी तक समझौता वार्ता के 23 दौर पूरे हो चुके हैं। कुछ लीक हुए दस्तावेजों से यह पता चलता है कि आरसीईपी के कारण दवाई, कर नीति, निवेशक अधिकार, और किसानों को बीज की उपलब्धता के ऊपर काफी गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। पिछले 6 वर्षों के समझौता वार्ता के दौरान, कभी भी आरसीईपी को लेकर भारतीय संसद में अभी तक कोई विशेष चर्चा नहीं हुई और न ही किसी राज्य सरकार से कोई परामर्श किया गया। हां, सदस्य देशों के कुछ गिने–चुने व्यापारिक समूहों से जरूर थोड़ी बहुत बातचीत की गई है।

दूसरी चिंता आसियान से है, जो इस समझौते के केंद्र में है। इस 16–सदस्यीय मुक्त व्यापार समझौते का उद्देश्य आसियान को एक समूह के रूप में संगठित करने का उतना ही है जितना यह आसियान का अन्य 6 देशों के साथ आर्थिक एकीकरण में गहराई और विस्तार लाने का है। भारत और आसियान के बीच पहले से ही एक मुक्त व्यापार समझौता चल रहा है जिससे भारत को अभी तक कोई फायदा नहीं मिला है। भारत–आसियान समझौते के कारण भारत का आसियान के साथ व्यापार घाटा वर्ष 2010–11 में 4.98 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2016–17 में 9.56 बिलियन डॉलर हो गया। इससे बड़ा ठोस प्रमाण और क्या चाहिए कि भारतीय उत्पादक इस मेगा 16–सदस्यीय व्यापार समझौते में अपने समकक्ष से प्रतिस्पर्धा कर पाने में सक्षम नहीं है। भारतीय कृषि एवं निर्माण क्षेत्र के लिए यह एक आपदा की तरह होगा। क्योंकि आरसीईपी के अंतर्गत करीब 92 प्रतिशत

उत्पाद शामिल हैं जिनके आयात शुल्क में भारत को कटौती करनी पड़ेगी।

तीसरी बड़ी चिंता यह है– चीन, जो इस मेगा व्यापार समझौते का एक प्रमुख सदस्य है। बिना किसी मुक्त व्यापार समझौते के ही चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2017–18 में 63 बिलियन डॉलर (चार लाख उनसठ हजार करोड रूपये) पहुंच चुका है जो 10 वर्ष पहले 2007–08 में केवल 16 बिलियन डॉलर था। भारत के बाजार पहले से ही चीनी उत्पादों से भरे पड़े हैं। इसका प्रभाव विशेष रूप से खिलौना उद्योग, ताला उद्योग, कपड़ा मशीनरी क्षेत्र, साइकिल निर्माण, डीजल इंजन पंपसेट तथा अन्य उद्योगों के ऊपर साफ देखा जा सकता है। 'एसोचैम' (एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़) ने भारतीय खिलौना उद्योग के ऊपर वर्ष 2013 में एक अध्ययन किया जिससे पता चलता है कि भारत के बाजार चीन से आयातित खिलौनों से भरे हुए हैं। इससे भारतीय खिलौना निर्माता पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। इसी प्रकार 'टैक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन' ने चीन से आयात होने वाले सस्ती कपड़ा मशीनों का विरोध किया क्योंकि वे 30 से 50 प्रतिशत तक सस्ते थे। भारत की साइकिल उद्योग भी चीन के आयात से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। 'यूनाइटेड बाइसिकल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन' के अनुसार 5–6 साल पहले (करीब 2008–09 में, लुधियाना से होने वाले कुल निर्यात की मात्रा करीब 1,500 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2013–14 में यह बदलकर उलटा हो गया। निर्यात के बदले अब करीब 1,500–2,000 करोड़ रुपए का आयात हो रहा है। आरसीईपी के तहत सीमा शुल्क में कटौती या कमी का भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के ऊपर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ेगा। यही नहीं बल्कि आरसीईपी में एक अन्य प्रावधान है जिसके तहत भारत अपने खनिज और कच्चे माल के ऊपर कोई निर्यात प्रतिबंध नहीं लगा सकेगा। इसकी वजह से कच्चे माल की घरेलू उपलब्धता के ऊपर खतरा मंडराने लगेगा और इससे अत्यधिक खनन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे कच्चा माल आधारित उद्योगों के बंद होने की भी संभावना है जिससे भारत में बेरोजगारी काफी बढ़ जाएगी। इसके साथ–साथ आरसीईपी के आने से पूरी संभावना है कि खाद्य निर्यात पर लगा प्रतिबंध (विशेष रूप से गेहूं और चावल के ऊपर) हटाना पड़ेगा, जो भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है।

दुग्ध उद्योग के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव भी भारत के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। आरसीईपी सदस्य देशों में से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दुग्ध उत्पादन में 'आक्रामक' रुचि है।

आरसीईपी से जुड़ी एक और प्रमुख समस्या यह है कि सदस्य देश विशेष रूप से जापान और दक्षिण कोरिया 'ट्रिप्स–प्लस' की मांग कर रहे हैं जिसका संबंध बीज, दवाइयों और कृषि रसायनों के ऊपर बौद्धिक संपदा सुरक्षा से है। यह भारतीय किसानों के लिए खतरनाक होगा। भारत इस वक्त यूपीओवी (यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वैराइटीज कन्वेंशन) का सदस्य नहीं है। पर इससे भारत के ऊपर यूपीओवी में सम्मिलित होने का दबाव बढ़ जाएगा और हमें यूपीओवी–1991 के मानकों का अनुपालन करना पड़ेगा। यूपीओवी बीज पेटेंट की एक व्यवस्था है जो किसानों के बीज और पौध सामग्री के संरक्षण और आदान–प्रदान के अधिकार को खत्म करता है। इससे सीधे–सीधे बीज संप्रभुता पर चोट पहुंचती है। यह कॉरपोरेट–ब्रीडर को प्राथमिकता देता है। शोध कार्य के लिए शोधकर्ताओं एवं दूसरे ब्रिडरों की आजादी को प्रतिबंधित करता है। ट्रिप्स–प्लस के प्रावधान भी बीज, कीटनाशक खाद और पशु टीका के ऊपर एकाधिकार स्थापित करते हैं और मालिकाना–कृषि (proprietary agriculture) तकनीकों को बढ़ावा देते हैं। ट्रिप्स–प्लस के प्रावधान बड़े कॉरपोरेट घरानों को एकाधिकार तो प्रदान करते हैं, पर वे किसानों और स्थानीय समुदायों के मौजूदा पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते। स्वास्थ्य क्षेत्र में ट्रिप्स–प्लस प्रावधानों का मतलब है – डेटा विशिष्टता (Data exclusivity) को स्वीकार करना, पेटेंट की शर्तों का विस्तार और उसके साथ–साथ इनका सख्त क्रियांवयन जिससे पूरा जेनेरिक (सामान्य) दवा क्षेत्र कमजोर पड़ जाएगा। ऐसे में केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विकासशील विश्व में जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता खत्म हो जाएगी। इससे दवाओं के ऊपर अनिवार्य लाइसेंस जारी करने का भारत सरकार का अधिकार भी सीमित हो जाएगा और हमें पेटेंट एक्ट से मिलने वाली स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों से हाथ धोना पड़ेगा।

दुग्ध उद्योग के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव भी भारत के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। आरसीईपी सदस्य देशों में से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दुग्ध उत्पादन में 'आक्रामक' रुचि है। अगर भारत सरकार दुग्ध उत्पादों के ऊपर सीमा शुल्क में कटौती करती है तो भारतीय दुग्ध उद्योग के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। दुग्ध

उत्पाद जैसे तरल दूध, मिल्क पाउडर, मक्खन, पनीर इत्यादि का न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। भारत के 15 करोड़ दुग्ध किसानों की तुलना में न्यूजीलैंड में केवल 12,000 और ऑस्ट्रेलिया में केवल 6,300 किसान हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जहां 156 मिलियन मेट्रिक टन दूध का रोजाना उत्पादन होता है जो घरेलू स्तर पर ही खपत भी हो जाता है। भारत से दूध या दुग्ध उत्पादन का निर्यात न के बराबर होता है। दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड 22 मिलीयन मेट्रिक टन का उत्पादन करता है जिसमें से 19 मिलियन मेट्रिक टन वह निर्यात कर देता है। ऑस्ट्रेलिया 15 मिलियन मेट्रिक टन का उत्पादन करता है और 4 मिलियन मैट्रिक टन का निर्यात करता है। यही वजह है कि दुग्ध कॉरपोरेट जैसे 'फोनटेरा' (न्यूजीलैंड) और सापूतो (ऑस्ट्रेलिया) की नजर आरसीईपी के ऊपर है जिससे उन्हें भारत के विशाल दुग्ध बाजार में प्रवेश मिल जाएगा। अमूल जैसे भारत के दुग्ध सहकारी संस्थान को डर है कि अगर दूध या दुग्ध उत्पादों के ऊपर से आयात शुल्क हटा दिया गया तो उससे न सिर्फ भारत का दुग्ध उद्योग और सहकारी संस्थान प्रभावित होंगे बल्कि इसका सीधा असर देश के 15 करोड़ दुध किसानों की आजीविका के ऊपर पड़ेगा।

भारत के दुग्ध सहकारी संस्थान को डर है कि अगर दूध या दुग्ध उत्पादों के ऊपर से आयात शुल्क हटा दिया गया तो उससे न सिर्फ भारत का दुग्ध उद्योग और सहकारी संस्थान प्रभावित होंगे बल्कि इसका सीधा असर देश के 15 करोड़ दुध किसानों की आजीविका के ऊपर पड़ेगा।

इसमें कोई शक नहीं है कि 16 देशों में व्यापार को प्रोत्साहित करने के नाम पर आरसीईपी खाद्य एवं कृषि क्षेत्र के साथ–साथ भारत जैसे देशों के फायदेमंद बाजार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में सौंप देगा। और तो और उनके अधिकारों और निवेश को सुरक्षित रखने के लिए, आरसीईपी में 'निवेशक–सरकार विवाद निपटान' (Investor-State Dispute Settlement – ISDS) का भी प्रावधान है, जहां निवेशक कंपनियां सरकारों के खिलाफ मुकदमा चला सकती हैं। अगर कोई सदस्य देश आरसीईपी के तहत किए गए प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं करता है तो कोई विदेशी कंपनी उससे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए उस सरकार के ऊपर मुकदमा चला सकती है। यह प्रावधान राष्ट्रीय सरकार की संप्रभुता और नीति–निर्धारण क्षमता के ऊपर सीधा आघात है। इसके जरिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में बेबुनियाद और निरंकुश शक्ति सौंपी जा रही है। भारत के ऊपर पहले से ही करीब 20 ऐसे मुकदमे चल रहे हैं, जहां निवेशकों ने भारत सरकार के ऊपर 'बाइलेटेरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़' (बिट) के तहत मुकदमा चला रखा है। अब भारत के ऊपर एक बड़ा दबाव होगा कि वह आरसीईपी के तहत 'निवेशक–सरकार विवाद निपटान' प्रावधान को स्वीकार करे।

यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले वर्ष की शुरुआत तक आरसीईपी के समझौतों को पूरा कर लिया जाएगा। इसीलिए यह अप्रत्याशित रूप से महत्वपूर्ण है कि इस मेगा समझौते से होने वाले खतरनाक परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। ❑❑

(अफसर जाफरी फोक्स ऑन द ग्लोबल साउथ, नई दिल्ली)

संदर्भ

1. बेस रेट (आधार दर) वह प्रयुक्त दर होता है जो किसी विशिष्ट वर्ष में सबसे पसंदीदा देश के ऊपर लगाया जाता है; इसे आपसी सहमति से तय किया जाता है।
2. बाध्यकारी दर, डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत वह सर्वोच्च दर या सीमा है जो एक देश अपने लिए तय करता है। यह ऊपरी सीमा होती है जिसे वह देश कभी पार नहीं कर सकता। इसके विपरीत 'प्रयुक्त दर' वह शुल्क है जो लागू हो रहा हो। प्रयुक्त दर कम भी हो सकता है पर वह कभी भी बाध्य दर से ज्यादा नहीं होगा। इसलिए बाध्यकारी दर का एक विशेष महत्व है क्योंकि वह सीमा शुल्क को बढ़ाने की देश की क्षमता को सीमित करता है।
3. एक बिलियन 100 करोड़ होता है। 30 अक्टूबर 2018 को एक डॉलर की कीमत 73 रुपया के बराबर थी, तो 3.6 बिलियन डॉलर = 3.6 X 100 X 73 = 26280 करोड़ रुपया।
4. आर.सी.ई.पी के विचार को पहली बार आसियान शिखर वार्ता के समय 2011 में पेश किया गया था। आर.सी.ई.पी वार्ताओं की औपचारिक शुरुआत आसियान शिखर वार्ता 2012 में हुई।
5. आर.सी.ई.पी के 16–सदस्यीय देशों में से केवल ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, सिंगापुर और वियतनाम ही यू.पी.यो.वी–1991 के सदस्य हैं। चीन और न्यूजीलैंड यू.पी.यो.वी के सदस्य तो है पर उन्होंने 1991 के प्रारूप पर हस्ताक्षर नहीं किया है।

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

— संपादक, स्वदेशी पत्रिका —

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

आर्थिक संकट में पाकिस्तान

पाकिस्तान को भारत में आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के रूप में जाना जाता है, वो पिछले लंबे समय से आर्थिक संकटों से गुज़र रहा है। हाल ही में उसके इस आर्थिक संकट ने भयंकर रूप धारण कर लिया है, और वह उसकी आर्थिक संप्रभुता के लिए भी ख़तरा बन रहा है। पिछले काफ़ी समय से चीन से उसका उधार बढ़ता जा रहा है, जिसे चुका सकने की क्षमता भी इसमें बची नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) का दरवाज़ा खटखटाया है, यदि अब पाकिस्तान आईएमएफ से ऋण लेता है तो आजादी के बाद पाकिस्तान ने एक दर्जन बार से भी ज्यादा बार आईएमएफ से मदद ली है। आईएमएफ सदैव की भांति अपनी शर्तें पाकिस्तान पर लादना चाहता है और शायद पाकिस्तान ने उसकी शर्तें मान भी ली हैं, जिसके कारण नव–निर्वाचित प्रधानमंत्री इमरान ख़ान अपने विपक्षियों की आलोचना का शिकार भी हो रहे हैं।

पाकिस्तान जो अभी भी भारत से शत्रुता की भावना से ग्रस्त है, जिसके जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधि अभी भी सेना के सामने बौने नजर आते हैं, जिसमें औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास न के बराबर है, जहां नागरिक सुविधाओं का भारी अभाव है, कैसे आज के जन की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा, यह बड़ा सवाल पाकिस्तान के सामने है।

– डॉ. अश्वनी महाजन

पाकिस्तानी रुपये की बदहाली

यूं तो पाकिस्तानी रुपया हमेशा से ही भारतीय रुपये से कमज़ोर रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में भारतीय रुपये के मुक़ाबले पाकिस्तानी रुपया काफ़ी अधिक कमज़ोर हो गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2007 में एक डॉलर लगभग 65 पाकिस्तानी रुपये के बराबर होता था, दिसंबर 2017 तक यह 106 रुपये प्रति डॉलर था और तबसे पांच बार अवमूल्यन के बाद आज यह 139 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। यदि देखें तो आज एक भारतीय रुपये के बराबर दो पाकिस्तानी रूपए हैं। पाकिस्तानी रुपये की यह बदहाली पाकिस्तान के बढ़ते व्यापार व भुगतान शेष घाटे के कारण हुई है। पिछले काफ़ी लंबे समय से भारी व्यापार घाटे व भुगतान शेष घाटे के कारण पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार संकट में है और अब तो यह ऋणात्मक दो अरब डॉलर तक पहुंच गया है। आज पाकिस्तान अपने पुराने विदेशी कर्ज़ को चुकाने की भी स्थिति में नहीं है। पाकिस्तानी उद्योगों की बदहाली और बिगड़ती क़ानून

व्यवस्था के चलते एक ओर उद्योग धंधे नहीं लग पा रहे हैं तो दूसरी ओर विदेशी निवेशक भी पाकिस्तान से मुँह मोड़ चुके हैं। पिछले काफ़ी समय से चीन पाकिस्तान में कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से जुड़े आयातों के बढ़ते जाने से ही उसके भुगतान शेष की समस्या में बिगाड़ आया है और पाकिस्तान पर चीन का कर्ज़ बढ़ता जा रहा है।

पाकिस्तान के बढ़ते कर्ज़ और बिगड़ती विदेशी मुद्रा भंडारों की स्थिति ने पाकिस्तान को और उधार लेने के लिए मजबूर कर दिया है और उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से उधार के लिए गुहार लगायी है। लेकिन यह तो सर्वविदित है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष जब भी किसी देश को उधार देता है तो उसके साथ कई शर्तें भी जुड़ी होती हैं। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन उसकी शर्तों को पूरा करने के लिए ही किया जा रहा है। हालाँकि पाकिस्तानी सरकार यह कह रही है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण लेने के अलावा अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है और हाल ही में उसे सऊदी अरब से एक अरब डॉलर का ऋण प्राप्त हो चुका है।

मामला मात्र पाकिस्तानी रुपये के अवमूल्यन का ही नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ती हुई महँगाई का भी है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर माह तक पाकिस्तान में महँगाई की दर 7.6 प्रतिशत तक पहुँच चुकी थी। यदि आइएमएफ की बात मानें तो अगले साल जून तक यह महँगाई की दर 14 प्रतिशत तक पहुँच सकती है। पिछले काफ़ी समय से पाकिस्तान में नीतिगत ब्याज दर भी लगातार बढ़ रही है और इस बार भी उसमें एक प्रतिशत वृद्धि होने की अपेक्षा है। आइएमएफ का कहना है कि अगले साल के मध्य तक पाकिस्तान में ब्याज दर 15 प्रतिशत तक पहुँच सकती है। इसका मतलब यह होगा कि पाकिस्तान में जीडीपी की ग्रोथ बहुत घट जाएगी अभी भी जीडीपी की ग्रोथ मात्र 3 प्रतिशत ही बतायी जा रही है। यानी कह सकते हैं कि एक तरफ़ बढ़ती महँगाई और दूसरी तरफ़ ग्रोथ की नीची दर, लगातार बढ़ता व्यापार और भुगतान शेष घाटा, पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है।

पाकिस्तान के बढ़ते कर्ज़ और बिगड़ती विदेशी मुद्रा भंडारों की स्थिति ने पाकिस्तान को और उधार लेने के लिए मजबूर कर दिया है और उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से उधार के लिए गुहार लगायी है।

पाकिस्तान के पास क्या हैं विकल्प?

हालाँकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान इस वादे पर प्रधानमंत्री चुनकर आए थे कि वे भ्रष्टाचारी अफ़सरों द्वारा विदेशों में रखे कालेधन को वापस लाएंगे और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेंगे। मित्र राष्ट्रों से ऋण लेने में तो उन्हें कोई समस्या नहीं है लेकिन यदि वे आइएमएफ से ऋण लेने का फ़ैसला करते हैं उन्हें आइएमएफ की शर्तों को मानना पड़ेगा। आइएमएफ की शर्तों में सबसे पहली शर्त यह होती है कि सरकारी खर्चों में किफ़ायत की जाए और राजकोषीय घाटे पर क़ाबू किया जाए। दूसरी शर्त होती है करेंसी का अवमूल्यन। स्वाभाविक तौर पर इमरान ख़ान इन शर्तों के लिए स्वेच्छा से तैयार नहीं होंगे क्योंकि ऋण लेते ही उनके खर्चों पर लगाम लग जाएगी। लेकिन विडंबना यह भी है कि उनको मित्र राष्ट्रों चीन और सऊदी अरब से कोई विशेष मदद नहीं मिल रही। ऐसे में उनके कूटनीतिक प्रयासों के विफल होने पर उनके पास आईएमएफ से ऋण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उससे ऋण लेने पर पाकिस्तान को तुरंत दो फ़ैसले करने होंगे एक अपनी करेंसी का और ज़्यादा अवमूल्यन और दूसरा खर्चों पर अंकुश। बढ़ती महँगाई के चलते उन्हें ब्याज दर में भी वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे पाकिस्तान का विकास भी बाधित होगा।

पिछले कालखंड में सेना के दबाव, भारी भ्रष्टाचार और चीन के आगे घुटने टेकते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के नाम पर बढ़ते कर्ज के चलते आज का पाकिस्तान संकट के भँवर में फँस चुका है और आर्थिक रूप से पाकिस्तानी हुक्मरानों के हाथ–पैर बंध चुके हैं। विदेशी कर्ज़ की अदायगी में कोताही का ख़तरा, विदेशी मुद्रा का संकट, खर्चों पर लगाम, करेंसी का लगातार अवमूल्यन, बढ़ती महँगाई आदि सभी पाकिस्तान की आवाम के लिए ख़तरे की घंटी है। इन समस्याओं से क्रिकेट की दुनिया से आये इमरान खान कैसे निपटेंगे, यह तो समय ही बतायेगा, लेकिन पाकिस्तान के वर्तमान हालातों को देखते हुए, यह काफी मुश्किल काम जान पड़ता है। पाकिस्तान जो अभी भी भारत से शत्रुता की भावना से ग्रस्त है, जिसके जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधि अभी भी सेना के सामने बौने नजर आते हैं, जिसमें औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास न के बराबर है, जहां नागरिक सुविधाओं का भारी अभाव है, कैसे आज के जन की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा, यह बड़ा सवाल पाकिस्तान के सामने है। कहीं वह चीन की साम्राज्यवादी नीति के सामने घुटने टेक देगा या अपनी संप्रभुता कायम रख पायेगा? यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। ❑❑

मोदी मंत्र

साफ नीयत, सही विकास

देर आए पर दुरूस्त आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केबिनेट द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा और नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की बात पर संसद ने मुहर लगा दी। संसद के दोनों सदनों में इस विषयक संविधान संशोधन पर भारी बहुमत के साथ इसे पारित कर दिया गया। निश्चित रूप से मोदी सरकार द्वारा उठाया गया यह एक ऐतिहासिक कदम है। मोदी का यह कदम समाज में बदलाव लाने और सबका साथ–सबका विकास की प्रतिबद्धता जताने के साथ–साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बार–बार आरक्षण पर दी जा रही राय को अमलीजामा पहनाने वाला भी है।

संसदीय राजनीति में ऐसे अवसर बिरले ही आते हैं जब सत्तारूढ़ दल कोई संविधान संशोधन जैसा कदम उठायें और विरोधी दल के पास समर्थन करने के अलावा और कोई विकल्प न हो। ऐसा ही नजारा बीते दिनों लोकसभा और राज्यसभा में सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी 124वें संविधान संशोधन के समय दिखा। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के सभी गरीब लोगों के स्वास्थ्य की मुक्कमल व्यवस्था करने के बाद केंद्र की राजग सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देकर अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की है।

'सबका साथ–सबका विकास' के सूत्र वाक्य के सहारे पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में बनी सरकार की अगुवाई कर रहे नरेंद्र मोदी ने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि उनके काम करने का मूलमंत्र होगा साफ नियत और सही विकास। सरकार के कामों का मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि वर्तमान सरकार ने भविष्य उन्मुख और लोगों की सतत भलाई के अनुकूल फैसले लिए है जो कि एक नए भारत की नींव रखने, उसे मजबूती देने का काम कर रहा है। स्वच्छता अभियान से शुरू कर आयुष्मान भारत कार्यक्रम तक सैकड़ों योजनाओं की एक लंबी फेहरिस्त है, जिनमें अधिकांश के मोर्चे पर सरकार की पहल का सकारात्मक असर हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में महात्मा गांधी के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में खुद झाड़ू उठाकर अभियान को

आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के सभी गरीब लोगों के स्वास्थ्य की मुक्कमल व्यवस्था करने के बाद केंद्र की राजग सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देकर अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की है।

– अनिल तिवारी

गति देते हुए लोगों से यह शपथ लेने की अपील की कि न गंदगी करेंगे, न गंदगी करने देंगे। इसका जनता में सकारात्मक असर हुआ। आज से 4 साल पहले प्रति 10 में से केवल चार घरों में शौचालय थे, 2018 बीतते–बीतते यह आंकड़ा प्रति 10 में से 7 घर तक पहुंच चुका है।

भारतीय योग पद्धति के बारे में कहा जाता है कि इससे केवल शरीर की ही नहीं बल्कि आत्मा और विचार की भी शुद्धि होती है। 11 दिसंबर 2014 को भारत की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकारते हुए 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। यह प्रस्ताव बिना किसी मतदान के स्वीकार कर लिया गया। सरकार की सूझबूझ और पहल पर संसद में लंबे समय से अटके पड़े वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी बिल को पारित कराकर 1 जुलाई से लागू किया गया है। इसे आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी सरकार का एक अति सराहनीय प्रयास रहा है। इस योजना के तहत भारत सरकार देश के आम गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवा रही है। लक्ष्य है कि बीतते–बीतते 6 करोड गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त में एलपीजी का कनेक्शन दे दिया जाएगा। हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान देश के अर्थ मंत्री अरुण जेटली ने आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए बताया कि जीएसटी से करदाताओं की संख्या में गुणात्मक बढ़ोतरी हुई है, वहीं उज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन के मामले में 80 प्रतिशत से अधिक का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री ने इस दौरान विश्व के कई देशों का दौरा कर भारत के मजबूत आर्थिक और सामरिक संबंध स्थापित किए। इन वर्षों में नरेंद्र मोदी जहां जहां भी गए वहां अपनी एक अलग छाप छोड़ी। एक तरफ पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए प्रचलित प्रोटोकॉल तोड़कर वहां के प्रधानमंत्री से मिलने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गए तो दूसरी तरफ दमदारी के साथ उसी पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके यह संदेश भी दिया कि विनम्रता का अर्थ कमजोरी नहीं है। अपने एक वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत राम, कृष्ण, बुद्ध और गांधी की विरासत वाला एक शांतिप्रिय, सत्य और अहिंसा में विश्वास करने वाला देश है, लेकिन हमारे विश्वास हमारी अपनी मजबूती से निर्मित है। कोई भी शत्रु अगर इसे चुनौती देता है तो हम उससे निबटने में भी उतने ही सक्षम है। भारत ने विश्व भर के लोगों को इसका सबूत 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में सर्जिकल हमला करके दिया था इस क्रम अगर चीन की बात की जाए तो चीन लगातार परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के समूह एनएसजी में भारत की स्थाई सदस्यता पर हमेशा से अड़ंगा लगाता रहा है। चीन के मोर्चे पर केंद्र की सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर कई बड़े फैसले लिए। इसमें सफलता मिली डोकलाम के मामले पर। भारत की मजबूती का ही नतीजा था कि चीन को पीछे हटना पड़ा।

केंद्र की सरकार ने सैनिकों की लंबे समय से लंबित वन रैंक वन पेंशन की मांग को भी पूरा किया है, वही जन धन योजना के जरिए करोड़ों गरीबों को बैंकों से जुड़ा है।

भारत ने वैश्विक स्तर पर सार्क दक्षिण एशियाई उपग्रह उपग्रह लांच कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है जिसका पाकिस्तान को छोड़कर सभी देशों ने स्वागत किया है। ज्ञान विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बीते सालों में सरकार की अगुवाई में हुए प्रयासों ने हमें एक ऊंचाई दी है तथा हम कई मामलों में विकसित देशों को भी पीछे छोड़ने में कामयाब हुए हैं।

इसी तरह केंद्र की सरकार ने सैनिकों की लंबे समय से लंबित वन रैंक वन पेंशन की मांग को भी पूरा किया है, वही जन धन योजना के जरिए करोड़ों गरीबों को बैंकों से जुड़ा है। यह एक अत्यंत कामयाब योजना साबित हुई है आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी देश की अधिकांश आबादी बैंकिंग व्यवस्था से दूर रही लोगों के पास एक बैंक बचत खाता भी नहीं था जन धन योजना के तहत जीरो बैलेंस पर बचत खाते खुलवाए गए सरकार की पहल से करोड़ों भारतीयों के इन खातों में 83203 करोड रुपए बैंकों में जमा हुए।

कोयला और स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में केंद्र की सरकार पूर्ण पारदर्शिता की नीति लेकर आई है, वहीं सन 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक के सिर पर एक छत मुहैया कराने का संकल्प लिया है। इसे अमलीजामा पहनाने के लिए वर्ष वार लक्ष्य तय किए गए हैं। हृदय की बढ़ती बीमारी से निपटने के लिए हार्ट स्टैंट की कीमतों में 80 प्रतिशत की

कटौती की गई है, वहीं सरकारी नौकरियों में रिश्वतखोरी को रोकने के लिए ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की नौकरियों में साक्षात्कार को पूर्णतया खत्म कर दिया गया है।

उज्जवला योजना के जरिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस कनेक्शन देने के साथ ही ही प्रधानमंत्री मोदी ने इन सालों में एक करोड़ से अधिक लोगों को गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित किया है जिस तरह अनाज की कमी होने पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर देश की जनता ने 1 दिन का खाना छोड़ दिया था, ठीक उसी तरह अमीर लोगों द्वारा गरीबों को गैस कनेक्शन दिए जाने हेतु सब्सिडी छोड़ने का क्रम अभी भी जारी है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने देश में वीआईपी कल्चर को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। अब सिर्फ एंबुलेंस फायर ब्रिगेड व पुलिस जैसी इमरजेंसी सेवाओं में लगी गाड़ियां ही नीली बत्ती का इस्तेमाल कर रही है।

इस्लामिक रीति रिवाज में तीन तलाक के जरिए कोई भी मुस्लिम शख्स अपनी पत्नी से छुटकारा पा सकता है। आमतौर पर यह देखा जाता रहा है कि तीन तलाक के बारे में मुस्लिम औरतें बहुत डरी–सहमी व दबी रहती है। इस संबंध में केंद्र की सरकार ने अपनी राय रखी और दलील दी कि आधुनिक भारत में किसी ऐसे व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती जो किसी समुदाय की आधी आबादी को डर के साए में जीने को मजबूर करें। उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक को गैरकानूनी ठहराते हुए अवैध करार दिया।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए सरकार ने ऋण की व्यवस्था की है इसके लिए लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नोटबंदी के बाद कैशलेस लेनदेन के लिए सरकार भीम एप लेकर आई है यह एक क्रांतिकारी कदम है इस एप से

मोदी सरकार ने नारियों के सशक्तिकरण के लिए भी कई घोषणा की है जिसमें उज्जवला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रमुख है। इसके अलावा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते का किया है।

अब तक करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं।

मोदी सरकार ने नारियों के सशक्तिकरण के लिए भी कई घोषणा की है जिसमें उज्जवला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रमुख है। इसके अलावा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते का किया है। इसके साथ–साथ गर्भावस्था में महिलाओं के पोषण के लिए 6000 रू. की व्यवस्था की है। मुद्रा योजना में दिए गए लोन में 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं लाभार्थी है। युवाओं के लिए भी सरकार इसकी लिस्ट स्टार्ट अप आदि के माध्यम से अवसर दे रही है।

राज्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रारंभ से ही अपना एक अलग नजरिया रहा है। उन्होंने हमेशा प्रदेशों के एक विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करने के लिए सहयोग दिया। नक्सलवाद के उन्मूलन आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा मजबूत करने जैसे कामों के लिए पर्याप्त आवंटन किया। छत्तीसगढ़ के धमतरी गांव की कुंवर बाई को आईकॉन बनाने के साथ ही गरीब रतनाबाई के पैरों में चप्पल पहनाकर साबित किया कि उनकी गरीबों के प्रति हमदर्द हमेशा है।

लोकतंत्र में यदि सबसे ऊंचे पद का व्यक्ति समाज के सबसे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का चरण पखारे तो इससे बड़ा प्रमाण लोकतंत्र के लिए कोई और नहीं दिया जा सकता। चरण पादुका योजना के जरिए प्रधानमंत्री ने यह कर दिखाया इसी तरह वयोश्री योजना के जरिए वंचित लोगों के जीवन में खुशियां भरने का काम देश में पहली बार बड़े पैमाने पर सरकार की पहल से संभव हुआ है। भारत में जीवन बीमा कराने के लिए कई एक कंपनियां पहले से मौजूद थी लेकिन सरकार की ओर से कोई बीमा पॉलिसी नहीं थी। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा के तहत 3 योजनाओं की घोषणा की गई जिसमें जीवन ज्योति बीमा योजना शामिल थी। अब तक लगभग 20 करोड़ लोग इस योजना में शामिल हो चुके हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना भी एक महत्वाकांक्षी योजना साबित हुई है।

उजाला योजना के जरिए देश में लगातार बढ़ती बिजली की मांग से निपटने के लिए साधारण बल्बों की जगह एलईडी के प्रयोग को बढ़ावा दिया है। सरकार का दावा है कि उजाला योजना के मई 2018 तक कम कीमत पर लगभग 30 करोड एलईडी बल्ब लोगों में बांटे गए। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत देश के उन हिस्सों में भी बिजली पहुंचाने का काम चल रहा है जहां अब तक रोशनी नहीं पहुंची थी।

जाते साल की यादों और नए साल के संकल्पों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम 'मन की बात' के 51वें संस्करण में साफ नियत और सही विकास के मंत्र पर प्रतिबद्धता जताते हुए सकारात्मकता को वायरल करने की अपील की है। आयुष्मान भारत योजना, गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिटी, असम में देश के सबसे बड़े रेल रोड ब्रिज की बात करते हुए उन्होंने वंचितों को अवसर देने तथा पीड़ितों को योजनाओं के जरिए

राहत पहुंचाने का भरोसा भी दिया है।

मोदी सरकार ने किसान कल्याण योजनाओं के तहत इतने कार्यक्रम शुरू किए हैं, जितने पहले किसी सरकार ने नहीं किए। सन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प के साथ कृषि क्षेत्र का निर्यात 60 अरब डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य सामने रखते हुए कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दी है। चाय, कॉफी, चावल के साथ–साथ अन्य वस्तुओं के निर्यात से वैश्विक कृषि व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इसके लिए नीति में जैविक उत्पादों के निर्यात पर लगे सभी तरह के प्रतिबंधों को हटाने पर भी जोर दिया गया है। केंद्र की एनडीए सरकार ने दलहन, तिलहन की खरीद में 13 गुना वृद्धि करने, लागत से डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की घोषणा के साथ बीज से बाजार तक की अनुपम पहल की है। किसान संपदा योजना से आपूर्ति ढांचे को मजबूत करने गन्ना किसानों को राहत पैकेज देने के साथ कृषि बजट में 2 गुना वृद्धि की है। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने वर्ष 2009 से 2014 के दौरान मात्र 1 लाख 21 हजार करोड रुपए दिए थे। वहीं मोदी सरकार ने 2014 से 2018 के बीच साढे 4 साल में ही 2 लाख 11 हजार 694 करोड रुपए दिए हैं। सोयल हेल्थ कार्ड, सिंचाई, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए किसानों को लगभग मुफ्त में फसल बीमा का लाभ दिया गया है। किसानों की वैकल्पिक आय बढ़ाने के लिए भी कई कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। बागवानी, दुग्ध उत्पादन आदि क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का काम शुरू हुआ है। हरित क्रांति, कृषि उन्नति योजना जारी रखने के साथ–साथ 2020 तक यूरिया की सब्सिडी को बरकरार रखा है। देश के चिन्हित 115 जिलों में गोबर धन योजना से गांव के समुचित विकास की रूपरेखा तैयार की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि कौशल योजना, किसानों को निर्बाध बिजली, भंडारण की सुविधा के साथ–साथ किसानों की उपज के सही दाम के लिए ई–कृषि मंडी योजना प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, खाद्य सुरक्षा मिशन सहित अनेकों योजनाएं शुरू की गई है।

कुल मिलाकर भले ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत से आधे अधूरे वादों पर जनता को आज भी जवाब देना है लेकिन उन के बहुत से कदम ऐसे रहे जो पहले कभी नहीं उठाए गए। स्वच्छता अभियान, जन धन, आयुष्मान भारत, उज्जवला, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, जैसी कई अन्य योजनाएं एक बेहतर भविष्य का खाका प्रस्तुत करने वाली साबित हुई है। वास्तव में मोदी सरकार ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया है सरकार चलाने की एक ऐसी दिशा दी है जिस पर आगे चलकर आने वाली सभी सरकारें देश का सुनहरा भविष्य गढ़ सकेगी। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें : **http://swadeshionline.in/**

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC: BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

किसानों को कीमत नहीं, आय चाहिए

नई दिल्ली में किसानों के एक बड़े विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद पंजाब के मानसा में सैकड़ों किसानों की विधवाएं इकट्ठा हुईं। मैंने वहां एकत्र हुए सैकड़ों लोगों के बीच बैठकर कई किसानों की विधवाओं की झकझोर देने वाली कहानियां सुनीं। हरित क्रांति की धरती पर सैकड़ों किसानों की विधवाओं को देखना और उनसे मिलना आसान नहीं था। जैसे ही वे अपनी दर्दनाक कहानियां सुनाने के लिए खड़ी होतीं (अक्सर वे माइक के सामने खड़ी नहीं होतीं), तो कुछ शब्द कहने के बाद ही रोने लगती थीं। उसके बाद की चुप्पी सब कुछ कह जाती थी। शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता होगा, जब मैं अखबारों में किसानों की आत्महत्या से संबंधित खबरें नहीं पढ़ता। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना; पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला और गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय, अमृतसर द्वारा कराए गए एक संयुक्त अध्ययन में घर–घर जाकर सर्वे कराने पर पता चला कि पंजाब में पिछले 17 वर्षों (वर्ष 2000 से 2017 तक) में 16,600 किसानों ने आत्महत्या की है। यानि कृषि में अग्रणी राज्य पंजाब में प्रतिवर्ष लगभग एक हजार किसानों और कृषि मजदूरों ने अतिवादी कदम उठाते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पंजाब के खेतों में निरंतर मृत्यु का नाच जिस तरह जारी है, उसी तरह पंजाबी विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अन्य अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि पंजाब के प्रति तीन में से एक किसान गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है।

जब विधवाएं अपनी पीड़ा और कठिन संघर्ष का बयान कर रही थीं, कि परिवार के अकेले कमाऊ व्यक्ति के चले जाने के बाद उन्होंने मुश्किल हालात का किस तरह सामना किया, तब मैं यह सोचकर हैरान हो रहा था कि जिस पंजाब को देश के खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है, वह किसानों की आत्महत्या की क्यारी में कैसे तब्दील हो गया है और यहां के करीब 98 फीसदी ग्रामीण परिवार कर्ज में क्यों हैं? इनमें से 94 फीसदी

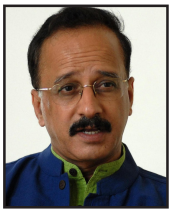

कषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) को किसान आय एवं कल्याण आयोग के रूप में परिणत करने की मांग होनी चाहिए, जिसके पास प्रति किसान परिवार को कम से कम 18,000 रुपये प्रति महीने निश्चित आय देने का अधिकार हो। सबका साथ सबका विकास की शुरुआत इसी से होगी।
– देविन्दर शर्मा

परिवारों का मासिक खर्च इनकी कुल आय से ज्यादा है। दूसरे शब्दों में, प्रगतिशील पंजाब के ग्रामीण परिवार कर्जों में जीते हैं। इंसान के लिए निरंतर साल–दर–साल, पीढ़ी–दर– पीढ़ी कर्ज में जीने से बदतर स्थिति दूसरी नहीं हो सकती। पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह ने ठीक ही कहा था कि किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में ही मर जाता है। उन्होंने जो नहीं कहा था, वह यह है कि जीवन भर कर्ज में जीना नरक में जीने जैसा है।

किसानों की विधवाओं की बातें सुनकर मैंने पहेली को सुलझाने की कोशिश की। फसलों के लिए निश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों के बकाया कृषि ऋण की माफी और सिंचाई नेटवर्क के विस्तार के जरिये किसी राज्य में कृषि की समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। लेकिन पंजाब में ये सहूलियतें तो पहले से ही हैं। यहां के 98 फीसदी खेतों में सिंचाई की व्यवस्था है और गेहूं, धान तथा मक्के की उत्पादकता में यह दुनिया में सबसे अव्वल है। फिर यहां के सैकड़ों किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? अगर उत्पादकता और सिंचाई मौजूदा कृषि संकट का जवाब है, तो पंजाब के किसानों के मरने का कोई कारण नहीं है। इससे यही साबित होता है कि भीषण कृषि संकट का कारण उत्पादकता और सिंचाईं से परे है।

और सबसे बड़ी बात यह कि पंजाब में खाद्यान्न की खरीद की एक व्यापक और विस्तृत प्रणाली है। एपीएमसी मंडियों और खरीद केंद्रों के साथ पंजाब में फसलों की खरीद के लिए देश भर में सबसे अच्छा बुनियादी ढांचा है। यहां गांवों को मंडियों से जोड़ने के लिए ग्रामीण सड़कों का विशाल नेटवर्क भी है। किसानों द्वारा मंडियों में लाए गए 98 फीसदी खाद्यान्न तय मूल्य पर खरीद लिए जाते हैं।

बयानबाजी से परे सुधारों की रणनीति तैयार करने के लिए भविष्य की ऐसी रूपरेखा बनानी होगी, जहां समाज छोटे और सीमांत किसानों को राष्ट्रीय बोझ न समझे।

सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने में किसान सक्षम हैं, जो मौजूदा बाजार कीमत से ज्यादा होता है।

इसके अलावा पंजाब ने हर छोटे एवं सीमांत किसान के अधिकतम दो लाख रुपये का कर्ज माफ करने की घोषणा की है। हालांकि चुनावी वायदा तो हर तरह के कर्ज (सहकारी, निजी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए कर्ज) माफ करने का था, लेकिन राज्य ने अब तक छोटे और सीमांत किसानों के लगभग 9,000 करोड़ रुपये के कर्ज माफ करने का वायदा किया है। इनमें से अब तक एक हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ भी किया गया है। इसके विपरीत महाराष्ट्र में शुरू में 34 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण माफ करने का अनुमान लगाया गया था, पर अब 14 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को माफ करने की योजना बनाई गई है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान में भी वायदे के विपरीत कर्ज के एक छोटे अंश को ही वास्तव में माफ किया जा रहा है। मुश्किल यह है कि राज्य सरकारों के पास उतने संसाधन नहीं हैं कि वे सभी कृषि ऋण माफ कर सकें। पंजाब में हर किसान की विधवा पर दो से 12 लाख रुपये तक का कर्ज है, जो उसके पति छोड़ गए थे। मैं यह जानकर हैरान रह गया कि बेहतर ग्रामीण बुनियादी ढांचा, सिंचाई और उन्नत प्रौद्योगिकी के बावजूद पंजाब की आर्थिक स्थिति इतनी बदतर कैसे हो गई!

ऐसे में, कृषि सुधारों को समझने, पुनः रणनीति बनाने और उसका सूत्र तैयार करने के लिए पंजाब एक बेहतर केस स्टडी बन सकता है। बयानबाजी से परे सुधारों की रणनीति तैयार करने के लिए भविष्य की ऐसी रूपरेखा बनानी होगी, जहां समाज छोटे और सीमांत किसानों को राष्ट्रीय बोझ न समझे। उन्हें परित्यक्त व्यक्ति के रूप में पेश करने के बजाय यह सुनिश्चित करने की चुनौती होनी चाहिए कि ग्रामीणों को कैसे लाभ हो सकता है और वे आर्थिक विकास का हिस्सा किस तरह बन सकते हैं।

फसलों की कीमत निर्धारित करने की नीति से अब हमें किसानों की आय निर्धारित करने की नीति की तरफ बढ़ना चाहिए। किसानों को निश्चित मासिक आय देने की जरूरत है, जो न केवल विश्व व्यापार संगठन के अनुसार हो, बल्कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करे। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) को किसान आय एवं कल्याण आयोग के रूप में परिणत करने की मांग होनी चाहिए, जिसके पास प्रति किसान परिवार को कम से कम 18,000 रुपये प्रति महीने निश्चित आय देने का अधिकार हो। सबका साथ सबका विकास की शुरुआत इसी से होगी।❑❑

किसान की समस्या पर नई सोच की जरूरत

आम चुनाव के सेमी फाइनल में किसान का मुद्दा छाया रहा है। केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में वृद्धि करके किसान का हित साधने का प्रयास किया था। लेकिन यह नीति सफल नहीं हुई है। इसके दो कारण हैं। मुख्य कारण यह है कि समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसान द्वारा फसलों का उत्पादन अधिक किया जा रहा है जबकि देश में खपत कम है। इस कारण फसल के दाम गिर रहे हैं और किसान घाटा खा रहा है। जैसे चीनी का उत्पादन अधिक होने एवम् खपत कम होने से चीनी का भण्डारण बढ़ता जा रहा है और दाम गिर हुए हैं। इस प्रकार समर्थन मूल्य बढ़ाने से समस्या का हल नहीं होता है।

दूसरा हल यह दिया जा रहा है कि बढ़े हुए उत्पादन का निर्यात कर दिया जाए, यहाँ समस्या यह है कि अधिकतर कृषि उत्पादों के विश्व बाजार में दाम कम हैं और अपने देश में अधिक। जैसे स्किम्ड मिल्क पावडर का विश्व बाजार में दाम 134 रुपया प्रति किलो है जबकि भारत में इसकी उत्पादन लागत 180 रुपए प्रति किलो है। ऐसे में यदि हमें स्किम्ड मिल्क पावडर का निर्यात करना है तो सरकार को 50 रुपया प्रति किलो कि सब्सिडी देनी होगी जो कि सरकारी बजट पर भारी पड़ेगा। यह नीति संभव नहीं है। साथ साथ उत्पादन बढ़कर निर्यात सब्सीडी देने से हमारे पर्यावरण की हानि होती है। जैसे हमने चीनी का उत्पादन अधिक किया। हमने अपने पानी का अति दोहन किया। भूमिगत पानी नीचे गिर गया। भूमि की उर्वराशक्ति कम हो गई। किसान ने मेहनत कि और लाभ उस विदेशी उपभोक्ता का हुआ जिसको हमने सब्सिडी देकर सस्ती चीनी उपलब्ध कराई। इसलिए निर्यात कि रणनीति सफल नहीं हो सकती है।

समस्या का तीसरा उपाय ऋण माफ़ी किया जाना है। देश के तमाम राज्यों ने किसानों के ऋण माफ़ किए हैं और इस चुनाव में भी ऋण माफ़ी के वायदे किए गए हैं। लेकिन यह भी सफल नहीं होगा जैसे घाटे में चल रही कंपनी के ऋण माफ़ कार दिए जैन तो शीघ्र

वर्तमान में आने वाले चुनाव में किसान का मुद्दा हावी रहेगा। सभी पार्टियों को वर्तमान समर्थन मूल्य, निर्यात एवम् ऋण माफ़ी की नीति को त्याग कर उच्च मूल्य के उत्पादन एवं किसान को सीधे सब्सीडी देने कि नीति को लागू करना चाहिए।

– **डॉ. भरत झुनझुनवाला**

की दोबारा घटा लगेगा और पुनः कंपनी ऋणमें डूब जायेगी। अथवा परिवार कि आय कम हो तो पुस्तैनी जेवर को बेचने से अधिक समय तक जीवित नहीं रहा जा सकता है। साथ साथ ऋण माफ़ी से राज्य सरकारों के बजट पर भारी वजन पड़ रहा है और राज्य सरकारें जरूरी विकास कार्य नहीं कर पा रही हैं जैसे सड़क आदि का बनाना। इस प्रकार वर्तमान में लागू तीनों हल यानि समर्थन मूल्यों की वृद्धि, निर्यात अथवा ऋण माफ़ी से किसानों कि समस्या हल नहीं हो रही है। हमें नई सोच की जरूरत है।

एक हल यह हो सकता है कि हम गेंहू और चीनी जैसे न्यून कीमत के कृषि उत्पादों के स्थान पर उच्च कीमत के कृषि उत्पादों की तरफ बढ़ें। आज फ्रांस में अंगूर की खेती करके शराब बनाई जा रही है। नीदरलैंड में ट्यूलिप फूलों की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है और संपूर्ण विश्व को वह देश ट्यूलिप के फूल उपलब्ध करा रहा है। अफ्रीका के छोटे से देश ट्यूनिसिया में जैतून के फलों की भारी खेती हो रही है। जापान में विशेष आकार के तरबूजों का उत्पादन किया जा रहा है। तरबूज के छोटे फल को एक विशेष आकर जैसे चकोर डिब्बे में डाल दिया जाता है जिससे बड़ा होने पर चोकोर आकार का बनता है। अमरीका में जीन परिवर्तन तकनीक के माध्यम से टमाटर के फल पर किसी कंपनी के लोगों को डाला जा रहा है। उन पौधों के हर फल के ऊपर उस कंपनी का लोगों स्वयं लगा हुआ हमें मिलता है। इस प्रकार के उच्च मूल्य के उत्पादों में किसान को भारी आय हो सकती है। फ्रांस और नीदरलैंड के किसान अपने कर्मियों को आज प्रति दिन सात हजार रुपए का वेतन दे रहे हैं चूँकि अंगूर और ट्यूलिप से इन्हें भारी आय हो रही है।

भारत के पास हर प्रकार की जलवायु उपलब्ध है। हिमालय से लेकर यदि हम डेकन के पठार और केरल तक पहुंचें तो गर्म, सर्द, नम और सूखे हर प्रकार की जलवायु हमारे यहां उपलब्ध है और हम अंगूर, ट्यूलिप, जैतून, तरबूज और टमाटर सभी की खेती आसानी से कर सकते हैं। हमें अपने किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के स्थान पर इन उच्च मूल्य के उत्पादों की तरफ ले जाना होगा। इसके लिए सरकार को कदम उठने होंगे। इंडियन काउन्सिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की शोध सस्थाओं को सही करना होगा। सरकारी वैज्ञानिक मुख्यतः कुर्सी पर बैठकर आराम करते हैं। इन संस्थाओं में स्वयं शोध करने को अधिक महत्व न देकर इनके द्वारा निजी युनिवर्सिटीयों को शोध करने के ठेके दिए जाने चाहियें जिससे कि वास्तविक शोध हो और भारत में फ्रांस के अंगूर जैसा उत्पादन हो सके।

हम अंगूर, ट्यूलिप, जैतून, तरबूज और टमाटर सभी की खेती आसानी से कर सकते हैं। हमें अपने किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के स्थान पर इन उच्च मूल्य के उत्पादों की तरफ ले जाना होगा। इसके लिए सरकार को कदम उठने होंगे।

साथ–साथ सरकार को इन कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए बुनियादी संरचना स्थापित करनी होगी। जैसे ट्यूलिप का फूल निर्यात करने के लिए नीदरलैंड के अमस्टरडाम हवाई अड्डे विशेष हेंगर बने हैं जहाँ पर वातानुकूलित वातावरण में इन फूलों को रखा जाता है और यंहां से इनका निर्यात हो सकता है। यदि आज हिमांचल के सोलन में ट्यूलिप फूलों की खेती हो तो उनको हवाईअड्डे पर लाकर विश्व के बाजार में पहुंचाना संभव नहीं है चूँकि हमारे हवाई अड्डों में इस प्रकारके वातानुकूलित हैंगरों की वयस्था नहीं है।

दूसरा उपाय यह है कि हम किसान को उत्पादन के अधिक मूल्य देने के स्थान पर वही रकम सीधे रकम सीधे उसके खाते में ट्रांसफर कर दें। अमरीका ने इस रणनीति को बखूबी अपनाया है। अमरीका के किसानों को भूमि पर खेती न करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। अगर कोई किसान अपनी भूमि को पड़ती छोड़ देता है तो रकम उसके खाते में डाल दी जाती है। अमरीका की सरकार समझती है कि यदि उत्पादन बढ़ेगा तो बाजार में सप्लाई बढ़ेगी और फसल के दाम घट जायेंगे। जैसे अमरीका में मक्के का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। मक्के का उत्पादन बढ़ा तो दाम गिर जायेंगे और किसान को घाटा होगा। उस घाटे की भरपाई करने के लिए अमरीका की सरकार यदि मक्के का समर्थन मूल्य बढ़ा दे तो उत्पादन बढ़ता जायेगा और उस उत्पादन को निर्यात करने के लिए सरकार को पुनः सब्सिडी देनी पड़ेगी। इसलिए अमरीका की सरकार ने निर्णय लिया कि मक्के का उत्पादन ही कम कर दो और किसान को एक रकम जमीन पर खेती न करने के लिए देने लगे। ऐसा करने से किसान को सीधे राहत मिली। उसकी जो उर्जा मक्के की व्यर्थ खेती करने के लिए व्यय होती थी उस उर्जा का उपयोग वह दूसरे कार्यों में कर रहा है।

वर्तमान में आने वाले चुनाव में किसान का मुद्दा हावी रहेगा। सभी पार्टियों को वर्तमान समर्थन मूल्य, निर्यात एवम् ऋण माफ़ी की नीति को त्याग कर उच्च मूल्य के उत्पादन एवं किसान को सीधे सब्सिडी देने कि नीति को लागू करना चाहिए। ❑❑

विकास के लिए सुदृढ़ वित्तीय आधारभूत संरचना आवश्यक

विकासशील देशों के लिए आर्थिक विकास के लिए जहां भौतिक आधारभूत संरचना जैसे–सड़क, पानी, बिजली इत्यादि आवश्यक है वहीं एक सुदृढ़ वित्तीय आधारभूत संरचना भी आवश्यक है। देश के आर्थिक विकास के लिए भौतिक व वित्तीय आधारभूत संरचना एक गाड़ी के दो पहियों के समान है। अब यदि ये संरचनाएं कम प्रमाणित व एक निश्चित स्तर से कम स्तरीय है तो विकास संभव नहीं हो पाता है, परंतु यदि विश्व स्तर की वित्तीय आधारभूत संरचना है तो विकास की गति बढ़ सकती है। इसलिए किसी भी विकासशाली देश (विकास के लिए प्रयत्नशील देश) को अपने यहां विश्वस्तीय वित्तीय आधारभूत संरचना की स्थापना पर अधिक से अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। इस श्रेणी में भारत भी अपने सभी प्रयास इस ओर कर रहा है। विकसित देश (जिनका पर्याप्त विकास हो चुका है) भी अन्य आधारभूत संरचनाओं के साथ–साथ वित्तीय आधारभूत संरचना की स्थापना के प्रयास करने के लिए उछलकूद करते रहते है।

जिस प्रकार खराब सड़कें आर्थिक स्थिति को कमजोर करती है उसी प्रकार अव्यवस्थित व असंगत वित्तीय आधारभूत संरचना भी देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है व लागत बढ़ाकर उद्यमियों के सम्मुख विकट बाधाएं खड़ी कर देता है, जिससे उद्यमी उद्योगों से पलायन करने लगते है। देश में कर संग्रह की स्वतः व्यवस्था जहां सरकारी खजाने को मजबूत करती है वहीं लागत को घटाकर तथा कागजी कार्यवाही को कम करके उद्यमियों को ऋण की व्यवस्था भी बहुत कम समय में कर सकती है।

एक क्रेडिट ब्यूरों उद्यमियों की ऋण लेने की क्षमता को जोखिम की गुणवत्ता पर तौलता हुआ निधारित कर देता है तथा उसको ऋण मिलना आसान हो जाता है। उद्यमियों के पास अच्छा अवसर आने पर उद्यमियों को कम समय में ऋण आसानी से उपलब्ध कराने में सुगमता प्रदान करता है। विश्वस्तरीय वित्तीय आधारभूत संरचना में निम्न तत्व होते हैं, प्रथम– यह परमाणु (एटमस) पर नहीं, बिट्स पर आधारित होती है। अर्थात जिसमें कागज

भारत में आधार कार्ड लागू होने से एक क्रान्तिकारी कार्य प्रारंभ हुआ है तथा ऋण लेने व देने में अब घोटालों पर अंकुश लगने लगा है। डिजिटल आईडेन्टीटी सिस्टम से भी भारत भी अब शीघ्र एक विश्वस्तरीय वित्तीय आधारभूत संरचना प्राप्त कर लेगा। इसमें अब कोई भ्रम नहीं रह गया है।

– डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

का कम प्रयोग होता है। द्वितीय– क्योंकि प्रक्रिया में देरी जटिलता उत्पन्न करके घोटालों को बढ़ा देती है अतः यह आसान होती है। तृतीय– ट्रांजेक्शन लागत कम करके आरोही क्रम को बढ़ावा देती है तथा ट्रांजेक्शन लागत को शून्य कर देती है। चतुर्थ– सौ प्रतिशत विश्वसनीय होती है तथा समय की बर्बादी से होने वाली हानि शुन्य होती है। इलैक्ट्रानिक तथा कागजी दोनों ही भुगतान तीव्र गति से होने के साथ सभी सिक्यूरिटीज के क्लीयरिंग सिस्टम पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देश में सिक्यूरिटीज के लिए डिपोजिटरी सिस्टम भी मजबूत होना चाहिए। विदेशी मुद्रा, डेरिबेटिब्ज, जिन्स तथा सिक्यूरिटीज क्रेडिट ब्यूरो को भी व्यापारिक आधार पर व्यवस्थित करना होगा। देश में कर संग्रह की भी व्यवस्था व्यवस्थित होनी परमावश्यक है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गत कुछ वर्षों से ही भारत में विश्वस्तरीय वित्तीय आधारभूत संरचना की स्थापना के प्रयास किये गये तथा भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा नेशनल डिपोजटरी विश्वस्तरीय वित्तीय आधारभूत संरचना के एक अच्छे उदाहरण माने जा सकते है। किसी भी लेनदेन के लिए कम खर्चीले तथा आसान तरीके को अपनाते है। यह म्यूचल फंड, धन प्रबंधन, डेरिबेटिब्ज, स्टॉक लेण्डिंग आदि कई प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते है। वित्तीय आधारभूत संरचना में सुधार के कई स्तरों पर प्रभाव पडता है। वित्तीय आधारभूत संरचना के साथ–साथ देश में सूचना सम्प्रेषण की आधारभूत संरचना भी सुदृढ़ होनी आवश्यक है। सेलफोन तथा गांव के एक छोटे खोखे से भी स्थानीय, राष्ट्रीय व अतंर्राष्ट्रीय कॉल को करने से इसको सर्वव्यापकता प्रदान करती है। नेश्डाक (NASDAQ) की तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यह दावा नहीं करती है कि वह भी उसकी तरह एक सौदे से दूसरे सौदे की तरफ उछलकूद करने में साहयता कर सकती है। भारत में इलैक्ट्रानिक क्लीयरिंग सिस्टम भी विकसित हो चुका है। परंतु इसमें भी बैच क्लीयरिंग सिस्टम को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

भारत में तेजी से वित्तीय सुधार करके आर्थिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। विकासशील देशों का सिद्धांत अब विश्वस्तरीय वित्तीय आधारभूत संरचना स्थापित करने की ओर चल पडा है।

राष्ट्रीय क्रेडिट ब्यूरो

उपभोक्ताओं, छोटे मझोले, व अति सूक्ष्म उद्यमियों व किसानों के क्रेडिट स्कोर का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट ब्यूरों का बनाया जाना आवश्यक है जिससे ऋण लेने में पर्याप्त आसानी, ऋण लेने का चक्रीय समय, एक ऋण लेने में लागत का आकलन, ऋण देने की सेवा में आने वाली लागत, ऋण लेने व देने वाले का न लाभ न हानि का बिन्दु का निर्धारण करना, ऋण देने के आधारभूत बिन्दु क्या होने चाहिए? ऋण वापस न देने के शून्य प्रतिशत मामले कैसे प्राप्त करें? व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से हानि की संभावनाएं क्या होनी चाहिए?

विश्वस्तरीय वित्तीय आधारभूत संरचना में तुरंत ऋण की सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है। व्यापारिक लेनदेनों में देरी की समस्या नहीं होनी चाहिए तथा व निधार्रित समय पर लेनदेनें का निपटारा किया जाता है। भारत में क्रेडिट ब्यूरों की स्थापना की गई है जोकि कंपनी तथा व्यक्तियों की ऋण लेने की क्षमता निधार्रित करके ऋण लेने की सुगमता निर्धारित हो जाती है। भारतीय साख सूचना ब्यूरो (CIBIL) यह कार्य करता है। CIBIL भारतीय राजनीतिक विधिक व आर्थिक परिस्थितयों को ध्यान में रख कर लोगों तथा भारतीय कंपनियों की ऋण क्षमता का निर्धारण करती है। स्थापना के प्रारंभ के दिनों में CIBIL को परेशानी का सामना करना पडा था परंतु अब वह अपने स्तर को विश्व स्तर तक ले जाने की निरंतर कोशिश कर रहा है किसानों के साथ–साथ उद्योगपतियों तथा बैंक खातेदारों की ऋण लेने की क्षमता का निर्धारण किया जा रहा है जिससे ऋण लेना व देना बहुत आसान हो गया है।

जिस प्रकार अमेरिका में प्रत्येक उपभोक्ता अपना क्रेडिट स्कोर जानता है उसी प्रकार भारत में भी लोग अपना–अपना क्रेडिट स्कोर जान सकेगें व इस ओर जागरूकता भी बढ़ती जा रही है तथा वे अपने क्रेडिट स्कोर में सुधार भी कर सकेगें। कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष विपणन (Direct Marketing) में यह क्रेडिट स्कोर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है।

भारत में आधार कार्ड लागू होने से इस ओर एक क्रान्तिकारी कार्य प्रारंभ भी हुआ है तथा ऋण लेने व देने में अब घोटालों पर अंकुश लगने लगा है। डिजिटल आईडेन्टीटी सिस्टम से भी भारत भी अब शीध्र एक विश्वस्तरीय वित्तीय आधारभूत संरचना प्राप्त कर लेगा। इसमें अब कोई भ्रम नहीं रह गया है। उद्योगपति, व्यापारी व स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में लोगों की ऊंगलियों के निशान अब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। भारत में तेजी से वित्तीय सुधार करके आर्थिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। विकासशील देशों का सिद्धांत अब विश्वस्तरीय वित्तीय आधारभूत संरचना स्थापित करने की ओर चल पडा है। ❑❑

लेखक सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर में वाणिज्य विषय में एसोसियेट प्रोफेसर के पद व प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त है व तथा स्वतंत्र टिप्पणीकार है।

जनता के लिए आर्थिक सुधारों की जरूरत

साल 2019 आशा का संदेश लेकर आया है, लेकिन आगे का रास्ता स्पष्ट नहीं है। अर्थव्यवस्था को नया रास्ता, पुनर्जीवन और जनोन्मुखी नीतियों की जरूरत है। यह पुनर्विचार का समय है। 'मनमोहनॉमिक्स'– उदारीकरण की मनमोहन सिंह की नीति ने सरकारों को असफल साबित किया है, इससे जनता का भला नहीं हो सका। कुछ हद तक मनमोहनॉमिक्स को अपनाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब सोचने को विवश है कि कहीं वह रास्ता तो नहीं भटक गई है। दूसरी ओर, आर्थिक नीतियों को लेकर कांग्रेस भी कोई राय ही नहीं बना पा रही है।

दरअसल, भाजपा को छोड़ कोई भी राजनीतिक दल नई आर्थिक दृष्टि को लेकर सहज नहीं है, न ही किसी के पास अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की कोई योजना है। टीएमसी, टीडीपी, बीएसपी, एसपी जैसे क्षेत्रीय दल हों या वामदल– ये सभी सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई में व्यस्त हैं। किसी के पास कोई आर्थिक विचारधारा नहीं रह गई है।

कोई भी विरोधी दल जनता और किसानों के लिए किसी योजना के साथ सामने नहीं आ रहा है। उनके पास उत्पादन और क्रयक्षमता बढ़ाने, रुपया को मजबूत करने और जब पेट्रोल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हो रही हों तो पेट्रोल के दाम को कम करने को लेकर कोई कार्यक्रम नहीं है। देश के लोगों में इस स्थिति को लेकर असमंजस का माहौल है।

जनता को नहीं मालूम कि आखिर किसानों की बदहाली को दूर करने के लिए कौन पहल करेगा। उन्हें यह भी जानकारी नहीं है कि बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद कर देने वाले और इस वजह से कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी के जिम्मेदार कॉरपोरेट के दखल को कैसे कम किया जाए। शिक्षा रोज–ब–रोज महंगी होती जा रही है। इस कारण, युवाओं में अनिश्चितता और गंभीर नकारात्मकता पैदा हो रही है। नौकरियां उनसे दूर भाग रही हैं। शिक्षा व्यवस्था को साफ–सुथरा करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। बढ़ते कोचिंग–ट्यूशन शुल्क और निजी विश्वविद्यालयों द्वारा आर्थिक तौर पर विद्यार्थियों को निचोड़ लेना स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई है। कुछ विश्वविद्यालय या संस्थान विद्यार्थियों पर अनुचित आर्थिक दंड लगाते हैं, जो कई बार तो कुल ट्यूशन शुल्क का कम से कम आधा होता है।

भाजपा को छोड़ कोई भी राजनीतिक दल नईआर्थिक दष्टि को लेकर सहज नहीं है, न ही किसी के पास अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की कोई योजना है।

– **शिवाजी सरकार**

आगामी लोकसभा चुनाव के पहले सिर्फ अंतरिम बजट लाया जाएगा। लोगों को आंकड़े तो मालूम हो सकते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होगा कि ये आंकड़े किस तरह लागू किए जाएंगे। देशवासी इस ऊहापोह में हैं कि अर्थव्यवस्था को मुक्त किया जा रहा है या यह सरकार के नियंत्रण में है, जैसा कि आरबीआई के नए गर्वनर शक्तिकांत दास मानते हैं। लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार को आरबीआई की परिसंपत्तियों में से हिस्सा लेने की जरूरत क्यों पड़ गई। जबकि, आरबीआई के रिजर्व धन पर किसी भी सरकार का कोई हक नहीं है।

अब लोग यह सवाल करने लगे हैं कि बैंकों से सरकार को कोई लाभांश क्यों लेना चाहिए, जबकि सरकार तो बैंकों में जमा जनता के पैसे की महज चौकीदार है। एक अच्छे

बैंकिंग सिस्टम में आय का निवेश जमाकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के इरादे से होना चाहिए, यह पैसा किसी और को नहीं दिया जाना चाहिए। जीएसटी को घटाए जाने के बावजूद टैक्स की दरें अभी भी ज्यादा हैं। कम आय वाले नौकरीपेशा लोगों और छोटे व्यवसायियों से भी टैक्स लिया जा रहा है। टैक्स की ऊंची दरें और 'टैक्स टेरर' यानी टैक्स के आतंक से आर्थिक गतिविधियों में गतिरोध बना हुआ है। पेट्रोल की कीमतें और टैक्स बढ़ाई जा रही हैं, तो दूसरी ओर तेल कंपनियों का मुनाफा जबर्दस्त तरीके से बढ़ रहा है। तेल कंपनियां उन गतिविधियों के लिए कैसे पैसा दे रही हैं, जो न तो व्यापार से जुड़ा है और न ही किसी सामाजिक हित से?

कुलमिलाकर, जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। सितंबर 2018 में किए गए एक 'गैलप सर्वे' यानी जनमत निर्धारित करने के लिए किए जाने वाले मतदान के मुताबिक, देश भर में भारतीयों के वर्तमान जीवन की रेटिंग पिछले कुछ समय की तुलना में सबसे खराब है। 0 से 10 के पैमाने पर 2014 में 4.4 के मुकाबले यह साल 2017 में 4.0 पर थी।

गैलप सर्वे के मुताबिक अपने जीवनस्तर को बेहतर मानने वाले भारतीयों के प्रतिशत में भी गिरावट आई है। साल 2014 में 14 प्रतिशत के मुकाबले साल 2017 में सिर्फ 3 प्रतिशत भारतीय ही अपने को समृद्ध मानते हैं। अर्धकुशल मजदूरों का वेतन जहां 2014 में 13300 रुपये प्रति माह था, वहीं वर्ष 2018 में यह घटकर 10300 रुपये रह गया।

ग्रामीण इलाकों में भी खाद्य सामग्रियां महंगी हुई हैं। गैलप सर्वे कहता है, "साल 2015 की शुरुआत में ही देश के ग्रामीण इलाकों में लोगों को खाद्य सामग्रियां खरीदने में कठिनाई होने लगी।" बताया गया कि 28 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण लोगों के पास 2015 में कई मौकों पर भोजन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। 18 प्रतिशत शहरी लोगों को भी ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा। यह स्थिति हर साल बदतर होती गई। ग्रामीण इलाके के 41 प्रतिशत लोगों और शहरी इलाकों के 26 प्रतिशत लोगों ने माना कि साल 2017 में भोजन का खर्च उठाने में वे असमर्थ रहे।

गैलप सर्वे ने ग्रामीण इलाकों में व्याप्त बेचैनी को स्वीकार किया है। किसानों की आत्महत्या निरंतर जारी है। कर्जमाफी के बावजूद कर्ज का स्तर अभी भी बहुत ज्यादा है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिए जाने के लिए किसी भी व्यवस्था को विकसित नहीं किया गया है। एमएसपी और वास्तविक कीमतों के बीच अंतर, जिसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 'भावांतर' कहा जा रहा था, की स्थिति में किसानों की शिकायतें कम नहीं हो पा रही हैं।

नोटबंदी के बाद नकदी की किल्लत हुई, लेकिन, आधिकारिक रूप से विकास होता हुआ दिख रहा है। विश्व मुद्राकोष के 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के साल 2017 के 6.7 प्रतिशत के मुकाबले 2018 और 2019 में क्रमशः 7.3 प्रतिशत और 7.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद जतायी है। दूसरी ओर, चीन की अर्थव्यवस्था की विकास दर के 2018 में 6.6 और 2019 में 6.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद जतायी गई है, जो साल 2017 में 6.9 प्रतिशत थी। लेकिन, यह भी सत्य है कि चीन की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना में कई गुना ज्यादा बड़ी है।

लोकसभा चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, नए साल में देश के परिदृश्य में ज्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं दिखती है। देश इस उलझन की स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा है। क्या 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले या बाद में देश उस सुनहरे रास्ते को ढूंढ पाएगा? दरअसल, यह आसान नहीं है। अफगानिस्तान और सीरिया से अमेरिका की वापसी नई चुनौतियों को जन्म देगी।

देश को वाकपटुता की नहीं, बल्कि एक राजनीतिक–सामाजिक दृष्टि की जरूरत है। दरअसल, नए जमाने के किसी भी दल के राजनेताओं में हालात से निपटने की बुद्धिमत्ता और कुशलता नहीं है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में बड़ी संख्या में पड़े 'नोटा' वोटों ने नेताओं के प्रति जनता के असंतोष को जाहिर किया है। नोटा को वोट देने वाले मतदाता या तो किसी दल को पसंद नहीं करते हैं या वे मानते हैं कि सभी दल समान रूप से देश की समस्याओं से निपटने में अक्षम हैं।

यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। चुनावों में अभी भी दो महीने से ज्यादा का वक्त बचा है। क्या इस अवधि में कोई बदलाव संभव है? इसे विडंबना ही कहेंगे कि निरंतर आर्थिक सुधारों और 'मेक इन इंडिया' के नारों के बीच देश के बाजार विदेशी सामानों से अटे पड़े हैं। इसके साथ ही, व्यापार घाटा बढ़ रहा है और नौकरियों में लगातार कमी आ रही है। सरकारी खर्चों में बढ़ोतरी के बावजूद आर्थिक तंत्र में आत्मविश्वास की कमी देखी जा रही है।

'नीति आयोग' के पहले अस्तित्व मे रहे 'योजना आयोग' का तो अपना एक निश्चित रास्ता था, लेकिन ऐसा लगता है कि नीति आयोग अभी भी स्थितियों से पार पाने के लिए रास्ता तलाशने में ही जुटा है। फिलहाल, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का तरीका खोजा जाना अभी भी बाकी है।

कहते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। भारतीय राजनीति में 2019 एक ऐतिहासिक साल साबित हो सकता है, और कौन जानता है कि निराश करने वाले हालात से ही कोई नया नेतृत्व और नई दृष्टि उभरकर सामने आ जाए। ❑❑

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम

एक तरफ तेल बिजली की किल्लत, तो दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग के चलते आज जब सारी दुनिया पर्यावरण के लिहाज से गंभीर खतरे का सामना कर रही है, तो सबका ध्यान ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर जाना लाजमी है। ऐसे में सूरज की रोशनी से मिलने वाली मुफ्त सौर ऊर्जा का अथाह भंडार कुदरत की तरफ से इस धरती को बख्शी गई सबसे बड़ी सौगात साबित होने जा रही है। ऊर्जा के लिहाज से सूर्य ईंधन का सबसे आदर्श रूप है। प्रमुख बात यह है कि सूर्य में अनंत ऊर्जा है, यह सर्वव्यापी है, यह सबसे शुद्ध है। सौर ऊर्जा को मानवता के लिए जीवनदायिनी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस के जलवायु सम्मेलन में 100 से अधिक सूर्यपुत्र देशों को एकजुट होकर इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन की घोषणा की। हमारे प्रयासों का परिणाम है कि वह 2014 में जहां हम केवल 13 मेगावाट उत्पादित कर पाए थे, वर्ष 2019 आते–आते 6000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर चुके हैं। सौर ऊर्जा के गर्भपाल से विकास की अनगिनत संभावनाओं को बड़ी तेजी के साथ चिन्हित किया जा रहा है। प्रगति के नए आयाम रोज–रोज जुड़ रहे हैं। हमारी सौर ऊर्जा यात्रा अब मेगावाट से बढ़कर गीगावाट का लक्ष्य हासिल करने के लिए हाथ पैर मारने लगी है।

वैश्वीकरण के दौर में ऊर्जा समस्त संभावनाओं और चुनौतियां का केंद्र बिंदु है। जीवन में ऊर्जा की जरूरत आज भी ऐसी ही है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई की है। दुर्भाग्यवश आज भी दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 21वीं सदी के मुख्य अविष्कारों का लाभ उठाने से वंचित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया का हर पांचवा व्यक्ति आज भी आधुनिक बिजली का उपयोग नहीं कर

वैश्वीकरण के दौर में ऊर्जा समस्त संभावनाओं और चुनौतियां का केंद्र बिंदु है। जीवन में ऊर्जा की जरूरत आज भी ऐसी ही है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई की है।
– **स्वदेशी संवाद**

भारत को अपनी बड़ी आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ ऊर्जा के स्वच्छ सस्ते तथा विश्वसनीय स्रोत की आवश्यकता है।

पाता है। जबकि 3 बिलियन की आबादी के घरों में विद्युतीकरण के बावजूद रसोई के कामों के लिए लकड़ी, उपले, कोयला तथा अन्य परंपरागत ऊर्जा पर निर्भर है।

इस स्थिति से उबरने के लिए महज अकेले या खोज के द्वारा आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इसके लिए हमें परंपरागत और आधुनिक दोनों तरह की सहभागिता चाहिए। सहभागिता का तात्पर्य प्रायः संगठन से होता है और संगठन मानवता, विकास और समावेशिता की सतत् आशा जगा सकते हैं। चूंकि भारत में उपभोग भी बढ़ रहा है, इस वजह से हमें सतत् ऊर्जा की अधिक आवश्यकता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घरेलू सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ–साथ वैश्विक स्तर पर सौर गठबंधन के प्रबल पक्षधर के रूप में उभरे है। आईएसए के माध्यम से भारत पूरे विश्व में सौर ऊर्जा का एक नया आयाम स्थापित करने की तरफ बढ़ रहा है।

भारतीय परंपरा में सूर्य को सभी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ऋग्वेद की ऋचाओं में कहा गया है कि भगवान सूर्य चल और अचल सभी वस्तुओं की आत्मा है। ऊर्जा क्षमता की पहचान कर भारत जैसा विकासशील देश जो प्रचूर सूर्य प्रकाश का धनी है, लेकिन विद्युत ऊर्जा की कमी के चलते अभी शापित है। हालांकि कमियों को दूर करने के प्रयास के साथ–साथ अपने ऊर्जा संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के द्वारा स्वयं को वैश्विक ऊर्जा के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने पर जोर है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में जितने भी तनाव के माहौल उत्पन्न हुए उनका कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध ऊर्जा जरूरतों और ऊर्जा संसाधनों पर अधिकार से था। शीत युद्ध हो, प्रथम खाड़ी युद्ध, द्वितीय खाड़ी युद्ध हो, क्यूबा अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप, इन सबके पीछे किसी न किसी रूप में ऊर्जा जरूरतें रही है। 21वीं सदी का पहला दशक तेल और कोल ऊर्जा के इर्द–गिर्द रहा। यह दोनों स्रोत अधिक दोहन के चलते समाप्त होने की कगार पर है। अब बात उस तत्व पर आकर रुक जाती है कि हम किस ऊर्जा के स्रोत पर निर्भर हो, जो हमारी बढ़ रही आवश्यकता को पूरा कर सके। तब हम इसके उत्तर में एकमात्र सौर ऊर्जा को विकल्प के रूप में पाते हैं।

पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने 59वें स्वतंत्रता दिवस पर कहा था कि ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि हमारे देश के सभी नागरिकों को जीवन भर हर समय किफायती ऊर्जा मिलती रहे। ऊर्जा की ऐसी आत्मनिर्भरता आवश्यक है जो तेल, गैस और कोयले के आयात से मुक्त हो। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 21वीं सदी के मध्य का योग उस देश का होगा जो अक्षय ऊर्जा को उत्पादित करने व इसके उत्पादन से संबंधित नीति निर्माण पर अपनी प्रभुता हासिल कर लेगा।

भारत को अपनी बड़ी आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ ऊर्जा के स्वच्छ सस्ते तथा विश्वसनीय स्रोत की आवश्यकता है। मालूम हो कि भारत एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहां सौर आतपन दर ऊंची है। यहां विश्व के अनेक देशों की तुलना में अधिक सौर प्रकाश मिलता है। यहां प्रति वर्ग मीटर की सतह पर 4 से 6 किलोवाट घंटा सौर विकरण प्राप्त होता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में कुल सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 750 गीगावाट के बराबर है।

वर्ष 2010 में राष्ट्रीय सौर मिशन शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 बनाना है। इस मिशन के जरिए कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने तथा कुशल व अकुशल दोनों प्रकार के समूह के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करने की बात कही गई। तीन चरणों में चलने वाले इस मिशन का लक्ष्य 2022 तक 20,000 मेगावाट की सौर क्षमता वाले ग्रिड को स्थापित करना है।

मिशन के पहले चरण में ऊहापोह रही, लेकिन दूसरे चरण में तेजी आई। एनटीपीसी और मेडा के माध्यम से काम की रफ्तार बड़ी साथ ही फोटो वोल्टिक कीमतों में गिरावट आ रही है वर्तमान सरकार ने इन बिंदुओं पर गौर किया और पाया कि ग्रिड क्षमता की संभावना बढ़ रही है और देश में ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में तेजी से वृद्धि हो रही है इसे देख सरकार ने जुलाई 2018 में वर्ष 2022 तक सौ गीगा वाट तक बढ़ाने का लक्ष्य कर दिया है। इसमें 7 गीगा वाट बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त होगा और 40 गीगा वाट ग्रिड

के माध्यम से जुड़ी सौर छतों से।

नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने 2022 तक 100 गीगावॉट कलश हासिल करने के लिए अनेक योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है। मंत्रालय ने 500 मेगा वाट और उससे ऊपर की छमता के साथ कम से कम 25 सोलर पार्क स्थापित करने की योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से 20000 मेगावाट क्षमता वालेसौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य है। वर्ष 2014 15 में प्रारंभ सौर पार्क अगले 5 साल में पूरे हो जाएंगे अब तक 21 राज्यों द्वारा 34 सोलर पार्क मंजूर किए जा चुके हैं।

इस क्रम में नहर के तटों और नेहरू के ऊपर सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी गई है। नहरों के ऊपर 50 मेगावाट और नहरों के तटों पर 50 मेगावाट के सौर संयंत्र की स्वीकृति के बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इस योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है।

रक्षा और अर्धसैनिक बलों के अधीन प्रतिष्ठानों में 300 मेगा वाट के ग्रिड से जुड़े स्वर यंत्र लगाने की योजना है। इस परियोजना को 5 वर्ष की अवधि के दौर प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी के जरिए शुरू किया जा रहा है इनमें से 150 मेगा वाट रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध कारखाना बोर्ड को आवंटित किया जाएगा इसी तरह सीपीएसयू और भारत सरकार के संगठनों द्वारा 1000 मेगा वाट की सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा अन आवंटित प्रारंभिक ऊर्जा के साथ बकलिंग तंत्र के तहत 3000 मेगा वाट बीएफ के साथ 2000 मेगा वाट की योजनाएं भी शुरू होने के कगार पर खड़ी है।

पिछले 5 वर्षों में 46 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ सौर क्षमता में इजाफा हुआ है वर्ष 2011 बारे में हमारी सौर क्षमता 1023 मेगावाट थी, जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर 6763 मेगावाट हो गई। भारत सौर क्षमता के मामले में दुनिया के शीर्ष 6 देशों में शामिल है और जल्द ही इसमें और सुधार होने वाला है।

हमारे नीति निर्माता ऊर्जा प्राचुर्य का लक्ष्य पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम नागरिकों के लिए भी आवश्यक है कि उर्जा का कम खपत वाले उपकरणों का प्रयोग करें, खाली कमरों में या घर से बाहर जाते समय बत्ती और पंखे बंद कर दे, ताकि ऊर्जा की बर्बादी ने हो।

भारत की विशाल सौर ऊर्जा क्षमता विद्युत का प्रमुख स्रोत बनेगी और प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा को पछाड़ देगी जो की तेजी से समाप्त हो रही है बढ़ती प्रतियोगिता और बड़े पैमाने पर हुए विकास ने सौर शुल्कों में भारी गिरावट की है सौर ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा की तुलना में बहुत प्रतिस्पर्धात्मक है हाल की रिवर्स बीडिंग के दौरान राजस्थान में एक परियोजना के लिए 4 रूपये 34 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की दर पर सबसे कम बोली लगाई गई थी।

भारत सरकार की अनुकूल नीतियों ने नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दरों को निर्धारित करने में सहायता की है सौर ऊर्जा की खपत बढ़ाने के लिए शुल्क नीति में संशोधन किया गया है और कहा गया है कि सी ई आई सी सौर ऊर्जा की खरीद के लिए न्यूनतम प्रतिशत को निर्धारित करेगी। शुल्क नीति राज्यों के लिए सौर ऊर्जा खरीदना अनिवार्य बनाएगी।

सरकार सौर सेल्स और सौर मॉडयूल के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने जा रही है। इससे घरेलू विनिर्माण में मदद मिलेगी, स्वदेशी उपकरण विदेशी सौर उपकरणों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उपलब्ध होंगे। राज्य के स्तर पर भी सौर ऊर्जा विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है।

100 गीगावाट की सौर ऊर्जा प्राप्त होने से 17 लाख 4 हजार 820 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का ह्रास होगा तथा लगभग 10 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा। अधिक रोजगार और निवेश के अवसरों से आमदनी बढ़ेगी। सौर ऊर्जा के बढ़े हुए लक्ष्यों से भारत में ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और देश की ऊर्जा सुरक्षा एवं ऊर्जा उपयोग में सुधार होगा। लक्ष्य को हासिल करने से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विनिर्माण की रफ्तार तेज होगी। सौर ऊर्जा के उत्पादन से पारंपरिक ऊर्जा का उत्पादन कम होगा और कोयला और गैस का आयात भी कम किया जाएगा जिससे विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी। विद्युत उत्पादन और विनिर्माण क्षेत्र द्वारा दिए जाने वाले कर से सरकार का राजस्व बढ़ेगा। साथ ही सौर योजनाओं के कारण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध बंजर भूमि का उत्पादक उपयोग किया जा सकेगा।

हमारे नीति निर्माता ऊर्जा प्राचुर्य का लक्ष्य पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम नागरिकों के लिए भी आवश्यक है कि उर्जा का कम खपत वाले उपकरणों का प्रयोग करें, खाली कमरों में या घर से बाहर जाते समय बत्ती और पंखे बंद कर दे, ताकि ऊर्जा की बर्बादी ने हो। बच्चों को एयर कंडीशन की बजाय सूरज की रोशनी और प्राकृतिक हवा में रहने की राय दें। यह सभी छोटे लगने वाले कदम बेहतर कल और सभी के लिए ऊर्जा के बड़े कारगर कदम साबित हो सकते हैं। ❑❑

भारत में एआई नवाचार में रोजगार की संभावनाएं (भाग-1)

ए.आई. (आर्टिफिशयल इटेंलिजेंस) यानि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् कम्प्यूटर क्षमता की तुलना में कुछ सैकंड में अरबों के डेटा (सूचनाएं) संसाधित (Processing) करना, डेटा के विस्तृत सेट को संग्रह (Store) करना और विश्लेषण (Analysis) करना जैसे कार्यों को संभव बनाती है। क्लाउड टेक्नोलॉजी के प्रसार से कम्प्यूटर की बढ़ी दक्षता के कारण कम्प्यूटर हार्डवेयर की बहुत कम लागत पर अधिक जटिल समस्याओं का समाधान करने और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। यह व्यक्ति के स्थान पर मशीनों की सीखने की क्षमता बढ़ाती है और अधिक बुद्धिमान (Intelligent) बनाती है। मशीन लर्निंग ने कम्प्यूटर के प्रदर्शन में महत्त्वपूर्ण सुधार किया है, जैसे स्मार्ट फोन को वॉयस एक्टीवेटेड सहायक द्वारा वॉयस कमांड का पालन करने में सक्षम बनाया है। एप्पल में सिरी और माइक्रोसॉफ्ट में कॉर्टाना–5 के उपभोक्ता अनुप्रयोगों (Applications) की शुरूआत हुई, परिणामस्वरूप अल्फागो कम्प्यूटर–6 जैसे नवाचारों (Innovations) के लिये मार्ग प्रशस्त हुआ है।

एआई विनिर्माण को रचनात्मकता और नवाचारों पर केन्द्रित करती है। एआई विनिर्माण (Manufacturing) संचालन को अधिक उन्नत एवं विश्वसनीय बनाती है क्योंकि यह मांग के पूर्वानुमान के अनुसार संचालन में त्वरित परिवर्तन, सटीक परिगणना (Scheduling) और श्रृंखला प्रबंधन को नियोजित कर सकती है। एआई सहायक प्रौद्योगिकी से विनिर्माण में उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा। आज कई देशों ने उद्योगों के ऐसे श्रम आधारित कार्यों में जिनमें मानव बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है, उन्हें रोबोट द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया है– जैसे वेल्डिंग, खनन एवं कारखानों के श्रमशील कार्य आदि। वित्तीय उद्योगों में कई वर्षों से मशीन लर्निंग द्वारा एआई निवेश सलाहकार के रूप

एआई में नवाचार और प्रसार के अनुकूल वातावरण निर्मित करने के लिये उपभोक्ता वस्तुओं (Consumer goods) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) से परे, सुनियोजित शिक्षा नीति को अपनाये जाने की आवश्यकता है तभी भारत में आगामी वर्षो की एआई क्रान्ति से रोजगार का अधिकतम लाभ प्राप्त करेंगे।

– डॉ. रेखा भट्ट

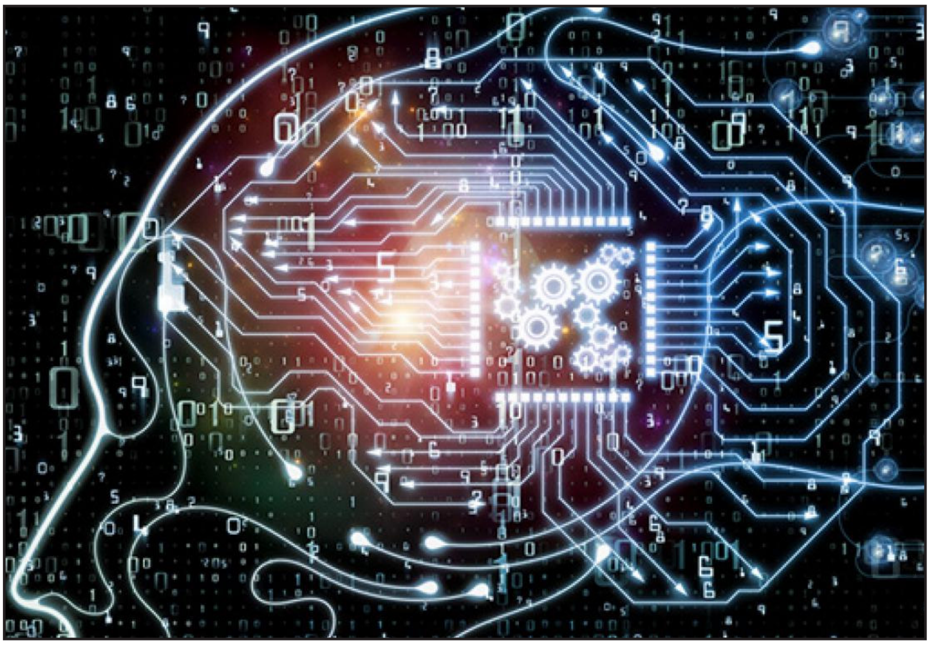

में कार्यरत है। एआई विनिर्माण से होने वाला सर्वाधिक लाभ 2030 में 26 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि के साथ चीन को होगा। चीन में इलेक्ट्रॉनिक के लिये दुनिया के सबसे बड़े अनुबंध निर्माताओं में से एक फॉक्सकॉन ने कुनशन क्षेत्र में केवल फॉक्सकॉन कारखाने में रोबोट द्वारा 60,000 श्रमिकों को प्रतिस्थापित कर दिया है और आगामी 10,000 औद्योगिक श्रमिकों को 30 से अधिक औद्योगिक रोबोट द्वारा प्रतिस्थापित करने का अनुमान है।

बैंक ऑफ अमेरिका–मेरिललिंच के एक शोध के अनुसार कई देशों में रोबोट का उपयोग मानव श्रमिक की तुलना में 15 प्रतिशत सस्ता होगा। वर्तमान में रोबोट से विश्व का 10 प्रतिशत विनिर्माण होता है जबकि 2025 में 45 प्रतिशत विनिर्माण कार्य रोबोट के हाथों में होगा।

वाणिज्यिक क्षेत्र में एआई प्रोद्योगिकी के बढ़ते प्रसार से आज भारतीय उपभोक्ता बहुत बड़ा लाभ उठा रहे हैं। अमेज़न मार्केट प्लेस और नेटफ्लिक्स जैसी ऑनलाईन सेवाओं की एक श्रृंखला का उपयोग करने के लिए, कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित विभिन्न अनुप्रयोगों से, भारत में उपभोक्ता एआई प्रसार के साथ आसानी से जुड़ गये हैं।

अनेक देशों में विनिर्माण कंपनियों में स्वचालन (Automation) से रोजगार पर असर होना शुरू हो गया है। भारत में एआई प्रौद्योगिकी की सम्पूर्ण क्षमता को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है यदि मानव श्रम की उपलब्धता का जनसंख्या लाभ उठाते हुए कम कुशल श्रमिकों को उन्नत विनिर्माण कार्यों के लिये प्रशिक्षित किया जाये। एआई आधारित विनिर्माण कार्यों को **'मेक इन इण्डिया'** जैसी प्रधानमंत्री योजनाओं में सम्मिलित करके भारत का **'विनिर्माण क्रांति'** का स्वप्न साकार किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी में सुधार होने से उत्पादों को आकर्षक व सस्ता बनाया जा सकेगा। नये प्रकार के कौशल द्वारा उत्पादकता बढ़ने से कामगरों को, आय बढ़ाने के अवसर बढ़ेंगे। श्रम उत्पादकता में सुधार से देश को प्रारम्भिक जीडीपी में लाभ होगा क्योंकि अधिकांश उद्योग एआई प्रौद्योगिकी से दो कार्यों की अपेक्षा करता है– पहला, श्रम द्वारा किये जा रहे कुछ कार्यों को स्वचालित करना और दूसरा, अपनी श्रम शक्ति की उत्पादकता में वृद्धि करना। इस तरह उपभोक्ता को उसकी सामर्थ्य अनुसार उत्पादों में विविधिता उपलब्ध होगी, उपभोक्ता मांग बढ़ेगी और उत्पाद सवंर्धन होगा। एआई संचालित विनिर्माण द्वारा उत्पाद संवर्धन से 45 प्रतिशत आर्थिक लाभ प्राप्त होगा जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ायेगा।

वर्तमान तकनीकी कौशल निकट भविष्य में अप्रासंगिक होने की आशंका है क्योंकि 2020 तक 70 प्रतिशत भारतीय कंपनियाँ एआई का लाभ उठाने लगेंगी और एआई पेशेवरों की अधिक मांग पैदा होगी।

वर्तमान तकनीकी कौशल निकट भविष्य में अप्रासंगिक होने की आशंका है क्योंकि 2020 तक 70 प्रतिशत भारतीय कंपनियाँ एआई का लाभ उठाने लगेंगी और एआई पेशेवरों की अधिक मांग पैदा होगी। वर्तमान तकनीकी पेशेवरों के एआई कौशल विकास द्वारा उन्हें रोजगार में पुनर्स्थापित किया जा सकेगा, जैसे IIMB में एआई मॉडल विकसित करने के प्रयास नए प्रकार के कौशल में रोजगार आपूर्ति कर सकेंगे। एआई में निवेश करने वाली ईवाई (EY) और नेसकॉम जैसी कंपनियों के अनुसार 2022 तक लगभग 46 प्रतिशत कर्मचारी पूरी तरह से ऐसे नये रोजगार में लगे होंगे जो आज उपलब्ध नहीं है तथा एआई कौशल द्वारा उत्पन्न नये कार्यों में संलग्न होंगे। अगले कुछ वर्षों में रोजगार के बदलते परिदृश्य के अनुसार भारत में कौशल बल को पर्याप्त कौशल प्रशिक्षण के साथ तैयार करने की आवश्यकता है।

तेजी से बदलते नवाचारों के साथ कुछ ही वर्षों के अंतराल में एआई रोजगार के कौशल अप्रचलित हो जाते हैं जिससे कंपनियों में नियोक्ताओं के रोजगार मापदण्ड भी बदल जाते हैं। आर्थिक विकास की प्रतिस्पर्धा में शिक्षा की वर्तमान अनुक्रमिक प्रणाली प्रासंगिक नहीं रह जाती। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भविष्य की एआई संचालित अर्थव्यवस्था पर आधारित शिक्षा का वैकल्पिक मॉडल लागू करना होगा तभी वर्तमान में हो रही एआई प्रगति देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी।

वैश्विक स्तर पर तेजी से बदल रहे आर्थिक माहौल के साथ रोजगार की प्रकृति भी निरंतर बदल रही है जैसे इंजीनियरिंग में विशिष्ट रूप से असंबंधित नौकरियों में बढ़ते इंजीनियरिंग स्नातकों की संख्या तथा व्यवसाय, प्रसंस्करण व आउटसोर्सिंग नौकरियों में कला और वाणिज्य स्नातकों की बढ़ती संख्या, इस बदलाव की पुष्टि करती है। अब आवेदक समय के साथ अनुकूलन करने और बढ़ते आर्थिक लाभ के परिवेश में प्रासंगिक बने रहने के लिये कैरियर के मध्य परिवर्तन करते रहना सामान्य हो गया है। इससे वर्तमान शिक्षा प्रणाली की निष्क्रियता स्पष्ट हो जाती है। एआई संचालित व्यवस्था में स्थायी रोजगार की अपेक्षा एक नियत समय तक वेतन की बजाय वित्तीय साधन प्रदान किया जायेगा जिसमें नियोक्ता एवं व्यवसायिक उच्च शिक्षण संस्थानों के आपसी सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। नियोक्ता भविष्य

में ऐसे आवेदक को नियोजित करने के लिये प्रतिबद्ध होंगे जो निश्चित समय सीमा पर कौशल में विशिष्ट दक्षता प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध होते हैं। इस प्रक्रिया में वर्तमान कौशल अधिग्रहण के समानान्तर मुक्त बाजार तंत्र का उपयोग करने का प्रयास होता है। मुक्त बाजार तंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि कौन से शिक्षण संस्थान विशिष्ट कौशल कार्यक्रमों को तैयार करते हैं। यह तंत्र दक्षता विकसित करने के इच्छुक छात्रों का समुचित मूल्यांकन भी करेगा।

आज प्रचलित अनुक्रमिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के जीर्णोद्वार की आवश्यकता है। भारत के निकट भविष्य में मशीन इंटेलीजेन्स संचालित अर्थव्यवस्था में चुनौतियों के लिये तैयार रहने और विश्व में सर्वाधिक युवा मानव पूंजी के कौशल को पुनः विकसित करने का एकमात्र माध्यम शिक्षा है अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल अर्थव्यवस्था का दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखते हुए शिक्षा प्रणाली की निरंतर प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना चाहिए। अगले कुछ वर्षों में वर्तमान शिक्षा प्रणाली रोजगार में बाधक बने उससे पूर्व, यथोचित प्रयोग करते हुए शिक्षा के नए स्वरूप का संचालन शुरू कर देना चाहिये। शिक्षा नीति में एआई क्रान्ति के लिये आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण की उपेक्षा किये जाने के कारण भारत में शिक्षा से जुड़े संस्थान, विद्यार्थी व शोधार्थी आज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

रोजगार मांग एवं कौशल आपूर्ति के बीच अन्तर को **'स्किल इण्डिया'** (कौशल भारत) जैसे रा ट्रीय कार्यक्रमों द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी (IT Sector) सेवाओं के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में एआई नवाचार को प्राथमिकता से सम्मिलित करना होगा। भारत में निवेश एवं नवाचार में कमी जैसी अनेक चुनौतियाँ होने के बावजूद युवा व प्रतिभा के जनसंख्या लाभांश द्वारा मानव पूँजी को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करना, एआई विस्तार का अद्वितीय अवसर प्रदान करता है।

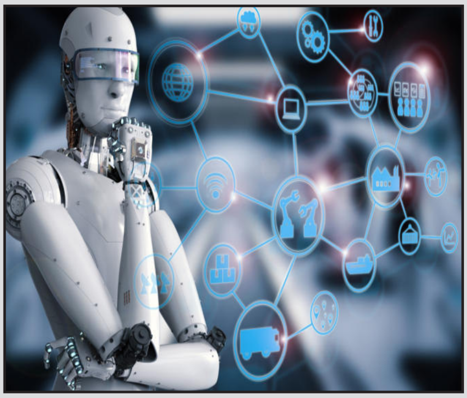

भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है अतः भविष्य की आर्थिक स्थिति एवं सुरक्षा व्यवस्था पर एआई प्रौद्योगिकी का विशिष्ट प्रभाव होगा।

सामाजिक व भावनात्मक क्षमताओं पर केंद्रित भाषा, कला, साहित्य, सांस्क तिक सम्बन्धी कार्य जो कम्प्यूटर द्वारा कभी भी उपलब्ध नहीं करवाये जा सकेंगे, वे कार्य सदैव मानवीय कौशल पर निर्भर रहेंगे। ऐसे कार्यों पर आधारित रोजगार जिनमें उच्च बौद्धिकता, रचनात्मकता और मानव सहानुभूति की आवश्यकता होती है, उन्हें एआई द्वारा अधिगृहित नहीं किया जा सकेगा। अतः भारत का मानव विकास और कौशल विकास की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास लाभदायक सिद्ध होगा।

भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है अतः भविष्य की आर्थिक स्थिति एवं सुरक्षा व्यवस्था पर एआई प्रौद्योगिकी का विशिष्ट प्रभाव होगा। असेंचर (Accenture) की एक रिपोर्ट के अनुसार एआई भारतीय अर्थव्यवस्था में 957 बिलियन डॉलर जोड़ने की क्षमता रखता है जिससे समग्र मूल्य वर्धित (Gross Value Added, GVA) की वार्षिक वृद्धि दर 1.3 प्रतिशत अंक बढ़ जाती है और 2034 में देश की आय में 15 प्रतिशत वृद्धि होगी।

चीन ने एआई के बुनियादी ढांचे के निर्माण का दृष्टिकोण रखते हुए नवाचार को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों के अनुकूल महत्वाकांक्षी परियोजनाएँ निर्मित कर ली है। परिणामस्वरूप सार्वजनिक लाभ द्वारा आर्थिक विकास का परिस्थितिकी तंत्र बीजिंग से सिलिकॉन वैली तक फैला दिखाई देता है। भारत में शिक्षण संस्थानों के पारंपरिक व सांस्कृतिक स्वरूप में नवाचार लाना महत्वपूर्ण होगा। भारत मशीन इटेलीजेंस का उपयोग करके डीप लर्निंग (Deep learning) की क्षमता विकसित कर सकता है तथा पूरे भारत में व्याप्त विशाल भाषायी विविधता के एक विशिष्ट भाषायीमंच देकर चीन की मेन्डेरिन से प्रतिस्पर्धा कर सकता है तथा तेजी से चीन से आगे एआई में अस्तित्व बना सकता है।

शिक्षण संस्थाओं में एआई हेतु आवश्यक संसाधन सामग्री द्वारा एआई अनुसंधान को आगे बढ़ाकर भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वव्यापी आधारभूत संरचना प्राप्त करेगा और तभी भारत अगले गूगल एवं माइक्रोसोफ्ट को जन्म दे सकता है।

एआई में नवाचार और प्रसार के अनुकूल वातावरण निर्मित करने के लिये उपभोक्ता वस्तुओं (Consumer goods) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) से परे, सुनियोजित शिक्षा नीति को अपनाये जाने की आवश्यकता है तभी भारत में आगामी वर्षों की एआई क्रान्ति से रोजगार का अधिकतम लाभ प्राप्त करेंगे। ❑❑

बहुसंस्कृतिवाद व आतंकवाद

– वैदेही तिवारी –

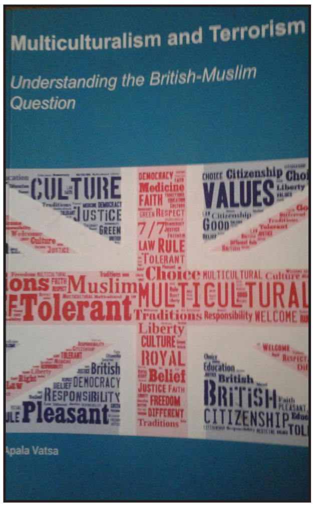

आज जब समूची दुनिया साम्राज्यवादी उग्र–राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों और धार्मिक सांप्रदायिक हिंसा की कार्रवाइयों के साथ–साथ विश्वयुद्ध के खतरे की ओर लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में एक भिन्न किस्म के राष्ट्रवाद के बहाने ब्रिटिश समाज में व्याप्त निचले दर्जे की असहिष्णुता की क्रूर सच्चाई बयां करती अपाला वत्स की पुस्तक मल्टीकल्चरलिज्म एण्ड टेररिज्म (बहुसंस्कृतिवाद और आतंकवाद) वहां की जमीनी हकीकत के साथ–साथ साम्राज्यवादी साजिशों एवं षडयंत्रों से संचालित फासीवादी राष्ट्रवाद के खतरे के तरफ भी ईशारा करती है। यह किताब 7/7 के बाद ग्रेट लगाकर बोले जाने वाले ब्रिटेन के भीतर छिन्न भिन्न हो रहे बहुसंस्कृतिवाद के साथ–साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बेहिचक धड़ल्ले से आतंकवादी करार दिए जाने विषयक घटनाओं का ज्वलंत दस्तावेज है। किताब में आंकड़े रिपोर्ट और जाने–माने लोगों के कोट के जरिए बताया गया है कि 7/7 के बाद ब्रिटेन की जनता में कूट–कूट कर छद्म राष्ट्रवाद भरने का काम सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है।

पाठक इस किताब के माध्यम से विश्व भर में लोकतंत्र के हिमायती और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचारित पहरूआ ब्रिटेन में इस्लाम बनाम ब्रिटेन विकसित पश्चिम बनाम पिछड़ा पूरब के संकट से गुजरता है। किताब के पढ़ते हुए कोई भी सजग पाठक उग्र राष्ट्रवाद के संभावित खतरे को भाप सकता है। अपाला भूमिका में लिखती हैं कि अमेरिका में हुए 9/11 के हमले के बाद पश्चिमी देशों में जो एक इस्लामोफोबिया फैली थी 7/7 के बाद ब्रिटेन में उसने अपनी जड़े जमा ली है। यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटिश मुस्लिम और ब्रिटिश नागरिक की बहस तेज हुई है। ऐसे में विविधता पसंद लोगों को कई तरह का नुकसान उठाना पड़ा है। गिने–चुने प्रतिक्रियावादी लोगों के चलते एक बड़ी आबादी को शक के दायरे में रखा गया है।

मालूम हो कि ब्रिटेन की कुल आबादी में लगभग आधे से अधिक नास्तिक लोग हैं जो बहुसंस्कृतिवाद के पक्षधर हैं। पिछले 20 वर्षों में चर्च आफ इंग्लैंड के बीस लाख (2000000) अनुवाई कम हुए हैं वहीं इसी अवधि में इस्लाम को मानने वालों की तादाद दस लाख (1000000) बढ़ गई है।

कंजरवेटिव पार्टी की चेयरमैन सईदा वारसी ने यह कह कर सनसनी फैला दी थी कि ब्रिटेन में मुसलमानों के खिलाफ पूर्वाग्रह डिनर टेबल टेस्ट पार कर चुका है। प्रस्तुत पुस्तक ने यह स्थापित करने की कोशिश की है कि ब्रिटेन में मुख्यरूप से दो तरह के लोग हैं। एक इंतिहापसंद रूढ़िवादी और दूसरा अति आधुनिक धर्म से दूर रहने वाला और इन दोनों के बीच सोंच रखने वालों को लगातार नजरअंदाज किया जाता है।

कुल पांच अध्यायों वाली इस पुस्तक में लेखिका ने ब्रिटेन में हुए 7/7 के हमले के बाद वहां रह रहे मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बारे में बारीक एवं गहन अध्ययन कर एक मुकम्मल यथार्थ प्रस्तुत किया है। किताब में उद्धृत एक पश्चिमी पत्रकार का कथन कि 'इस्लाम एक है और इस्लाम खतरनाक है' डर पैदा करता है तो एक अन्य विशेषज्ञ की राय कि 'नो वन इज माइनारटीज' थोड़ा संबल प्रदान करती है।

कुल मिलाकर धर्म और तिजारत के यथार्थ में चहलकदमी करती अपाला वत्स की यह एक ऐसी किताब बन पडी है जिसमें दिए गए तमाम प्रमाणिक आंकडे सूचनाएं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत का काम कर सकती है। किताब पढ़ते हुए पाठक आतंक के नाम पर हो रहे भेदभाव को नजदीक से महसूसता है। वहीं साम्राज्यवाद की साजिशें परत दर परत खुलती हैं। बाजारवादी–राष्ट्रवाद और उन्मादी–राष्ट्रवाद के समक्ष मानवता के लहूलुहान होने का जिक्र जबरदस्त है। सहज शैली में लिखी पुस्तक की भाषा इतनी प्रांजल और रोचक है कि पृष्ठ दर पृष्ठ पाठक स्वमेव आगे बढ़ता जाता है। वे जो बोल नहीं सकते और वो जो सुन नहीं सकते को समर्पित अपनी 162 पृष्ठ की पुस्तक में अपाला वत्स ने बहुसंस्कृतिवाद और आतंकवाद के परिपेक्ष में ब्रिटिश–मुस्लिम तथा बहुसंख्यकों के बीच अल्पसंख्यकों के सवाल को समझने की दृष्टि दी है। ❑❑

पेटेंट एक्ट में हो बदलावः स्व.जा.मंच

देश की शीर्ष अदालत द्वारा मोनसेंटो के कपास बीज पेटेंट के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद स्वदेशी जागरण मंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पेटेंट को नियंत्रित करने वाले नियमों में एक विधायी संशोधन की मांग करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मोनसेंटो को एक निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक फाइबर में आनुवंशिक रूप से संशोधित कपास के बीज पर पेटेंट का दावा करने की अनुमति दी है।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा है कि "सरकार को इस पूरे मामले पर गौर करने और इन कंपनियों को पेटेंट राशि वसूलने के लिए कानून में संशोधन करने की जरूरत है।" उन्होंने यह भी कहा है कि देशहित को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी जागरण मंच पेटेंट नियमों में विधायी संशोधन के लिए मांग करेगा तथा जरूरत पड़ी तो इसके लिए देश में जनजागरण भी करेगा।

आर्थिक सुधार नीति से पिछड़ गया देश : स्वदेशी जागरण मंच

शहर के बोधवन तालाब स्थित निजी होटल में स्वदेशी जागरण मंच का जिला सम्मेलन आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक अरुण ओझा ने संबोधित करते हुए कहा कि विगत 23 वर्षों से आर्थिक सुधारों से अपना देश पिछड़ता गया है। उदारवादी आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव पड़ा है। 1991 में देश की अर्थव्यवस्था व उत्पाद तंत्र को वैश्विक व्यवस्था से समेकित

करने का प्रतिकूल असर पड़ा। भारतीय उद्योग निर्मित सामान व घरेलू उत्पादन बंद होने के कगार पर पहुंच गए। शीतल पेयजल 70 से 80 प्रतिशत, टूथपेस्ट, जूते की पॉलिस, स्वचलित वाहन, फ्रीज 60 से 65 प्रतिशत विदेशी कंपनी के नियंत्रण में है। इसके पूर्व जिला सम्मेलन का उदघाटन भारत माता के तैल चित्र पर दीप प्रज्ज्वलन व राष्ट्रीय गीत के साथ हुआ। उन्होंने लोगों से स्वदेशी सामानों का उपयोग करने की अपील की। इस अवसर पर विचार मंडल प्रमुख बिहार राज्य संजीव सिंह, मुरारी झा, अनिल साहा, अनिल कुमार, पवन दुबे, अमरजीत कुमार, विवेक सिंह आदि मौजूद थे।

https://www.jagran.com/bihar/jamui-jamuinews-18786874.html

निजी बैंक भारतीय हाथों में ही हों: स्वदेशी जागरण मंच

स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर को देश में निजी बैंकों के मालिकाना हक के लिये नियामकीय मसौदे पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि वे भारतीय हाथों में बने रहें। रिजर्व बैंक के नये गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यभार संभालने के बाद संगठन ने यह बात कही।

स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने 'भारत में बैंकों का भविष्य' विषय पर एक चर्चा का आयोजन किया। इसका संचालन सह–संयोजक अश्विनी महाजन ने किया। परिचर्चा के बाद रिपोर्ट जारी की गयी। इसमें एसजेएम ने कहा, ''आरबीआई के नये गवर्नर के लिये निजी बैंक के मालिकाना हक मामले में नियामकीय मसौदे पर पुनर्विचार की जरूरत है। हममें से कोई यह नहीं चाहता कि भारत में विकसित बैंकों को विदेशी इकाइयों के हाथों में जाने की अनुमति दी जाए।'' संगठन ने यह कहा कि प्रवर्तकों की हिस्सेदारी की सीमा पर भी फिर से विचार किया जाना चाहिए। अनिवार्य रूप से हिस्सेदारी में कमी के लिये मौजूदा दिशानिर्देश उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि इससे विदेशी कोषों को भारतीय बाजार में पैठ बनाने में मदद मिल रही है। एसजेएम ने कहा कि देश को समाज की समावेशी वृद्धि के लिये मजबूत बैंकों की जरूरत है।

https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/private-bank-remains-in-indian-hands/articleshow/67079210.cms

छोटी व मझोली उद्योग इकाइयों को राहत

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सूक्ष्म, लघु व मझोले (एमएसएमई) क्षेत्र की इकाइयों को नए साल का गिफ्ट दिया है। उसने 25 करोड़ रुपये तक के मौजूदा कर्ज लौटाने में नाकाम रहीं इकाइयों को कर्ज पुनर्गठन की अनुमति दी है। कर्ज पुनर्गठन की सुविधा सिर्फ उन कंपनियों को मिलेगी

जिनके कर्ज अभी भी स्टैंडर्ड असेट्स के तौर पर वर्गीकृत हैं।

आरबीआइ के इस फैसले से उन एमएसएमई इकाइयों को राहत मिलेगी जो नोटबंदी और जीएसटी के चलते नकदी की किल्लत से जूझ रही हैं। आरबीआइ के बोर्ड ने 19 नवंबर की अहम बैठक में सुझाव दिया था कि आरबीआइ 25 करोड़ रुपये तक के दबावग्रस्त लेकिन स्टैंडर्ड असेट्स के पुनर्गठन के लिए अपनी योजना पर दोबारा विचार करे। लेकिन यह कदम इस तरह उठाया जाए कि वित्तीय स्थिरता बरकरार रहे।

आरबीआइ ने एक बयान में कहा कि एमएसएमई इकाइयों को दबावग्रस्त लोन खातों में राहत देने के लिए केंद्रीय बैंक ने उनके कर्ज के एक बार पुनर्गठन की अनुमति दी है। यह सुविधा उन इकाइयों को ही मिलेगी जो एक जनवरी 2019 को लोन चुकाने में नाकाम रहीं लेकिन उनके कर्ज स्टैंडर्ड असेट की श्रेणी में हैं। असेट क्लासिफिकेशन घटने पर यह सुविधा नहीं मिलेगी। इस योजना में सिर्फ वे ही इकाइयां पात्र होंगी जिन पर बैंक और एनबीएफसी से सभी तरह के कर्ज एक जनवरी 2019 को 25 करोड़ रुपये से अधिक न हों। उनके कर्ज का पुनर्गठन 31 मार्च 2020 तक किया जाएगा।

एमएसएमई के कर्जो के पुनर्गठन का मुद्दा सरकार और आरबीआइ के बीच काफी गरम रहा था। वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने 19 नवंबर की आरबीआइ बोर्ड की बैठक में एमएसएसई सेक्टर में नकदी किल्लत पर विस्तृत प्रजेंटेशन दिया था। सरकार ने इस सेक्टर को मदद पहुंचाने के लिए कई सुझाव दिए थे। देश के मैन्यूफैक्चरिंग में एमएसएमई की हिस्सेदारी करीब 50 फीसद है। आरबीआइ के इस फैसले पर स्वदेशी जागरण मंच के विचारक और आरबीआइ बोर्ड के सदस्य एस. गुरुमूर्ति ने ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी कि देश के छोटे उद्योगों के लिए यह बड़ा कदम है। कर्ज चुकाने में नाकाम होने पर इन इकाइयों को कामकाज चलाना बहुत मुकिश्ल हो गया है। उन्होंने आरबीआइ को इसकी घोषणा के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि 12 करोड़ रोजगार देने वाले एमएसएमई को इससे बड़ी राहत मिलेगी।

https://www.jagran.com/business/biz-rbi-gives-relief-to-msmes-allows-restructuring-of-loans-up-to-rupees-25-crore-18811565.html

महज 7 प्रतिशत युवाओं को मिलता है रोजगार

स्वदेशी जागरण मंच गुड़गांव द्वारा विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय सेक्टर–44 में आयोजित जिला सम्मेलन में मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल ने युवाओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि देश में हमेशा सरकारी नौकरियों का अभाव रहा है। सरकारी और अर्ध सरकारी सहित मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से महज 7 फीसदी युवाओं को ही रोजगार मिलता है। अन्य युवाओं को कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण नौकरी करना होती है। इसमें भी युवाओं को पर्याप्त मेहनताना नहीं मिलता। इस तरह से देश के करीब 41 फीसदी युवा ब्राउन फील्ड रोजगार में हैं। युवा अपने स्तर को ऊंचा करने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्वरोजगार अपनाएं।

विशिष्ट अतिथि विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर राज नेहरू ने कहा कि कौशल विश्वविद्यालय युवाओं को विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है, ताकि अधिकाधिक युवा भविष्य बेहतर कर सकें। कार्यक्रम में आरएसएस के प्रांत संघचालक पवन जिंदल, मंच जिला संयोजक बिक्रमादित्य, सोहना विधायक तेजपाल तंवर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य सुरेंद्र सिंह, आचार्य पुरोहित संघ अध्यक्ष पंडित अमरचंद भारद्वाज, मंच के प्रांत संयोजक सतेंद्र सौरोत, सह प्रांत कार्यवाह प्रतिमा मनचंदा, विभाग संयोजक उमेश आर्य मौजूद रहे।

https://www.bhaskar.com/harayana/gurgaon/news/only-7-of-youth-get-employment-020541-3575828.html

भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने का प्रयास कर रहा स्वदेशी मेला

नगर के टाउन हाल मैदान में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आयोजित दस दिवसीय मेला में स्वदेशी निर्मित वस्तुओं की खरीद बिक्री बढ़ गई है। किसानों को जैविक खेती के लिए जागरूक किया जा रहा और वही सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से समाज से दूर हो रही भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने का प्रयास स्वदेशी जागरण मंच की ओर से किया जा रहा है। मेले के नौंवे दिन पूर्व चिकित्साधिकारी डा. बद्रीनारायण व डा.अभिषेक गुप्ता की टीम ने निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया। मरीजों का नेत्र परीक्षण व निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण किया गया। इनका आपरेशन नगर के शांति नेत्रालय में जल्द ही किया जाएगा। रविवार को छुट्टी होने के कारण मेले में लोगों की भारी उमड़ी रही। मेला अंतिम पड़ाव पर होने के कारण शहरवासियों ने स्वदेशी वस्तुओं की जमकर खरीदारी की। मुख्य अतिथि मारकंडेय राय व रमेश चंदा रहे।

https://www.jagran.com/uttar-pradesh/ballia-indigenous-fair-trying-to-keep-indian-culture-alive-18803921.html

दंतोपंत ठेगड़ी की मनी जन्म शताब्दी

स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक दंतोपंत ठेगड़ी की जन्म शताब्दी को धूमधाम से मनाई गई। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क ज्ञानपुर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में काशी विभाग के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री कश्मीरी लाल ने उनके योगदान पर प्रकाश डाला। कहा कि वर्तमान समय

मेक इन इंडिया का नहीं है बल्कि मेड बाई इंडिया का है। काशी प्रांत गोरक्षा के प्रांत संयोजक आनंद श्रीवास्तव ने कहा कि हमें स्वदेशी को वाणी और व्यवहार में उतारना होगा। विभाग संयोजक आनंद कुमार शुक्ल ने मातृभाषा और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर जोर दिया। उपस्थित जनों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस दौरान स्वामी सुमित, विजय श्रीवास्तव समेत अन्य थे।

https://www.jagran.com/uttar-pradesh/bhadohi-celebrated-birthday-of-danthopanth-thangari-18793734.html

स्वदेशी दिवस के रुप में मनी बाबू गेनू की पुण्यतिथि

स्थानीय महावीर स्थान कुराइच में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा वीर बाबू गेनू की शहादत को स्वदेशी दिवस के रूप में मनाया गया। अध्यक्षता अधिवक्ता राष्ट्रीय परिषद सदस्य गंगेश्वर तिवारी व संचालन जिला संयोजक देवराज कुमार ने की। श्री तिवारी ने कहा कि 1930 को आज ही के दिन वीर बाबू गेनू ने मुंबई के कालबा देवी रोड पर विदेशी वस्तुओं से भरे ट्रक को रोकते हुए अपनी शहादत दी थी। उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक व महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। विभाग संयोजक लालबहादुर दूबे ने कहा कि दुनिया में व्यक्ति नहीं बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्य को ही याद किए जाते हैं। बाबू गेनू ने ऐसा कार्य किया है, जिससे वे अमर हो गए हैं। इस अवसर पर स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग व विदेशी उत्पादों के बहिष्कार का संकल्प लिया गया। मौके पर विनोद चौबे, लक्ष्मी कांत पांडेय, अमन राज, अनिष बहादुर, उज्ज्वल तिवारी, रविरंजय साहू, राजश्री राज, अमर कुमार समेत अन्य शामिल थे।

https://www.jagran.com/bihar/rohtas-death-anniversary-of-mani-babu-genu-as-swadeshi-day-18743793.html

किसानों को प्रति एकड़ दस हजार रुपये की राहत!

मोदी सरकार 2019 आम चुनाव से पहले किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। इस कदम के तहत सरकार किसानों को प्रति एकड़ सालाना 10,000 रुपए देने का ऐलान कर सकती है। किसान इस पैसे से बीज, खाद और खेती में काम आने वाली दूसरी चीजों पर खर्च कर सकते हैं। उपज की सही कीमत न मिलने से किसानों की हालत खराब है ओर इसको लेकर किसानों में सरकार के खिलाफ नाराजगी है।

सूत्रों के मुताबिक सरकार चुनाव से पहले ऐसी स्कीम लाना चाहती है जिससे आम चुनाव से पहले किसानों को सीधा फायदा पहुंचाया जा सके। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की कर्ज माफी से इनकार कर चुके हैं। उनका कहना है कि इससे किसानों को खास फायदा नहीं होता है। ऐसे में सरकार किसानों को हर साल प्रति एकड़ 10,000 रुपए मुहैया कराने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि इस स्कीम को चुनाव से पहले कम समय में लागू किया जा सकता है। और पैसा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस यानी 26 जनवरी को किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय इसके लिए संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों से जरूरी आंकड़े मांग रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय किसानों को हर साल एकमुश्त रकम मुहैया कराने वाली तेलंगाना और उड़ीसी में चल रही स्कीम का अध्ययन भी कर रहा है।

https://money.bhaskar.com/news/MON-MMTP-UTLT-modi-government-on-farmers-6004318-NOR.html

विजय माल्या भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित

आखिरकार विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया। अब उनकी संपत्तियों को जब्त किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। मुंबई में एक स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला लिया और इस प्रकार विजय माल्या देश का पहला भगोड़े आर्थिक घोषित हो गया। एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की एक अपील पर यह फैसला लिया गया। भारतीय बैंकों के 9 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के बकाएदार इन दिनों देश से फरार हैं और लंदन में रह रहे हैं।

गौरतलब है कि बीते साल अगस्त में नया भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून लागू हुआ था और इसके तहत माल्या देश का पहला आर्थिक अपराधी घोषित हो गया है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट से माल्या को भगोड़ा घोषित करने का अनुरोध किया था। साथ ही उनकी संपत्तियां जब्त करने और उन्हें नए एफईओ एक्ट के तहत केंद्र सरकार के कंट्रोल में लाने का अनुरोध किया था।

स्पेशल जज एम.एस. आजमी ने माल्या और ईडी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कानून के सेक्शन 12 के

अंतर्गत माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया। माल्या पर लोन रिपेमेंट के डिफॉल्ट करने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। वह मार्च, 2016 में देश से भाग गए थे।

https://money.bhaskar.com/news/MON-ECN-POLI-MRKT-court-declares-vijay-mallya-a-fugitive-economic-offender-6004546-NOR.html

बैंकों के विलय से ज्यादा बचत का मौका

बैंकों का विलय एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है और इससे होने वाले बदलावों को लेकर उन बैंकों के कर्मचारी और ग्राहक फिक्रमंद रहते हैं। खासकर उन बैंकों के ग्राहकों को अपने निवेश और कर्ज में आने वाले उतार–चढ़ाव की चिंता रहती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि कमजोर बैंकों का अगर मजबूत बैंकों में विलय होता है तो ग्राहकों के लिए फायदे का सौदा है। मजबूत बैंक खाताधारकों के लिए लंबी अवधि में जमा पर ज्यादा आकर्षक ब्याज दे सकते हैं और कर्ज की दरें भी कम कर सकते हैं। चूंकि बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया और देना बैंक का विलय एक अप्रैल से पूरा हो जाएगा।

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक की मजबूत स्थिति है और उसके साथ कमजोर देना बैंक का विलय नए बैंक के ग्राहकों के लिए घाटे का सौदा नहीं है। इससे एसबीआई और एचडीएफसी के बाद देश के तीसरे सबसे बड़े बैंक का उदय होगा। अल्पावधि में भले ही बैंकों के खाताधारकों की मौजूदा निवेश योजना या ज्यादातर कर्ज स्कीमों की दर पर तो कोई फर्क न पड़े, लेकिन नया बैंक लंबी अवधि की रणनीति के तहत जमा पर अच्छी ब्याज दर की पेशकश कर सकता है क्योंकि नए बैंक की परिसंपत्ति ज्यादा होगी, एनपीए कम होगा और कारोबार बढ़ेगा। साथ ही होम लोन, ऑटो लोन जैसी कर्ज की दरों को घटा सकता है, इससे ग्राहकों को सीधे तौर पर राहत मिलेगी।

इन बैंकों के छोटे शेयरधारकों को भी विलय से चिंता करने की जरूरत नहीं है। निजी संपत्ति सलाहकार कंपनी एडेलवेस के प्रमुख राहुल जैन का कहना है कि विलय की शुरुआत में भले ही मजबूत बैंक के शेयरों में कुछ गिरावट दिखे, लेकिन स्थिरता के बाद उन्हें भी फायदा होगा। ऐसे में छोटे निवेशकों को शेयर बेचने की हड़बड़ाहट से बचना चाहिए और थोड़े समय के लिए धैर्य रखना चाहिए।

केंद्र ने पहले ही भरोसा दिया है कि सरकारी बैंकों के विलय की प्रक्रिया में कोई छंटनी नहीं होगी। बैंक ऑफ बड़ोदा के साथ दो अन्य बैंकों के विलय पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इनमें एक बैंक की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी और उसका विलय दो मजबूत बैंकों के साथ किया गया है। दो बैंकों के विलय से बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन जाएगा। उन्होंने भरोसा दिया कि कमजोर बैंकों के विलय से मजबूत प्रतिस्पर्धी बैंक उभरेंगे और ग्राहकों इससे सस्ता कर्ज मिल सकेगा।

https://www.livehindustan.com/business/story-savings-chance-more-from-bank-merger-2348491.html

म्युचुअल फंड इंडस्ट्री की संपत्ति में 1.24 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी

एसआईपी निवेश में लगातार तेजी से वर्ष 2018 में म्युचुअल फंड के प्रबंधन के तहत परिसपंत्तियां 1.24 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई। एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड इन इंडिया (एम्फी) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, म्युचुअल फंड उद्योग की ओर से प्रबंधित परिसंपत्तियां दिसंब, 2018 के अंत तक साल भर पहले के 22.37 लाख करोड़ रुपये से 5.54 फीसद यानी 1.24 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 23.61 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

बता दें कि लगातार छठे साल म्युचुअल फंड उद्योग के प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (एयूएम) में वृद्धि हुई है। हालांकि, 2017 की तुलना में 2018 में धीमी गति से वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 में उद्योग की प्रबंधित संपत्ति 32 फीसद यानी 5.4 लाख करोड़ रुपये बढ़ी थी। क्वांटम म्युचुअल फंड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) जिम्मी पटेल ने कहा कि 2018 में म्युचुअल फंड की संपत्ति में खुदरा निवेशकों की मजबूत भागीदारी से तेजी आई है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को शिक्षित बनाने के सेबी के प्रयासों तथा एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड इन इंडिया के 'म्युचुअल फंड सही है' अभियान ने भी इसमें मदद की। म्युचुअल फंडों का मानना है कि नए साल में भी उनकी प्रबंधित संपत्ति में वृद्धि का रुख जारी रहेगा।

https://www.jagran.com/business/biz-mutual-fund-add-rupees-1-24-lakh-crore-to-asset-base-in2018-18828202.html

प्रत्यक्ष कर में रिकार्ड वृद्धि

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल–दिसंबर (2018) की अवधि के दौरान डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14.1 फीसद बढ़कर 8.74 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है। इस दौरान आयकर विभाग ने 1.30 लाख करोड़ रुपये का रिफंड किया। यह रिफंड पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि से 17 फीसद ज्यादा है।

आलोच्य अवधि के दौरान अग्रिम कर संग्रह भी पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14.50 फीसद बढ़कर 3.64 लाख करोड़ रुपये रहा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "दिसंबर 2018 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि यह

पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 14.10 फीसद अधिक होकर 8.74 लाख करोड़ रुपये रहा है।"

वहीं शुद्ध कर संग्रह (रिफंड के समायोजन के बाद) 13.60 फीसद बढ़कर 7.43 लाख करोड़ रुपये रहा है। चालू वित्त वर्ष के बजट में 11.50 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह से अभी तक बजट लक्ष्य की 64.70 फीसद कर प्राप्ति हुई है। कॉरपोरेट कर की सकल प्राप्तियों में 14.8 फीसद तथा व्यक्तिगत आयकर की सकल प्राप्तियों में 17.2 फीसद की वृद्धि रही है। रिफंड के बाद कॉरपोरेट करों के संग्रह में 16 फीसद की तथा व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 14.8 फीसद की शुद्ध वृद्धि हुई है। मंत्रालय की ओर से कहा गया, "यह जिक्र किया जाना जरूरी है कि पिछले वित्त वर्ष के कर संग्रह में आय खुलासा योजना के तहत प्राप्त अतिरिक्त राशि भी शामिल थी जो कि इस बार नहीं है।"

https://www.jagran.com/business/biz-direct-tax-mop-up-rises-more-than-14-percent-to-more-than-8-lakh-crpre-in-apr-to-dec2018-18828489.html

चौपाल से महिलाएं हो रहीं सशक्त : गोयल

चौपाल स्वाभिमानी 500 महिलाओं को लघु ऋण देकर समाज सेवा व देश को उज्ज्वल बनाने में सार्थक भूमिका निभा रहा है। वहीं 51 ई–रिक्शा देकर पर्यावरण सुधार को सही दिशा दे रहा है। यह उद्गार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चौपाल की ओर से स्वतंत्रता सेनानी श्री गोपाल फाउंडेशन द्वारा आयोजित 80वें लघु ऋण वर्ग वितरण समारोह में कहीं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कल्याणकारी योजनाओं में महिलाओं तथा निर्धन कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान से देश मजबूत हुआ है, जोकि समाज सेवा का सही मिशन है। हमारा उद्देश्य सबका साथ सबका विकास है, जिससें विश्व में तेज गति की अर्थव्यवस्था बनी। शहर–गांव में शौचालय, सफाई, बिजली की सुविधाएं से सारे देश को विकसित किया है। उन्होंने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव शिव कुमार के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. मदनलाल खुराना व स्वतंत्रता सेनानी श्री गोपालजी के प्रेरक अनुभवों को भी शेयर किया। आज चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी नहीं रहे व पूर्व मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना जी भी नहीं रहे, लेकिन दोनों महापुरुष आज भी हम लोगों के दिलों में रहेंगे। इनके द्वारा किए गए कार्य लोगों के लिए आज भी सर्वोपरि है।

अपनी भूली बिसरी यादों को याद करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के सचिव शिव कुमार ने अपने 50 वर्षों का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में जिस वक्त वह आए उन दिनों मदन खुराना, केदार नाथ साहनी

और विजय मल्होत्रा के परिवारों का सानिध्य मिला था। उन्होंने यह भी कहा की चौपाल कार्यक्रम बहुत सराहनीय है।

चौपाल योजना शानदार है। चौपाल संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि वह महिलाओं को सम्मान जनक ऋण मुहैया करना। जब समाज की महिलाएं सशक्त होंगी, तभी समाज सशक्त होगा, क्योंकि महिलाओं के बिना समाज, परिवार एवं देश अधूरा है। उक्त बातें उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर आदेश गुप्ता ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि चौपाल द्वारा जिन भी महिलाओं को ऋण मिला है, उन्होंने समय से इसे वापिस किया है।

साथ यह भी कि अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो घर सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। शनिवार को 80वें चौपाल कार्यक्रम में 500 महिलाओं को 10–10 हजार के चैक दिए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि चौपाल सस्ते रोजगार ऋण देने व महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रही है। वहीं मदनलाल खुराना की पुत्रवधू वंदना खुराना ने कहा कि महिलाओं को ऋण देकर अपने पैरों पर खड़ा करना एक महान कार्य है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने का काम चौपाल कर रही है। अगर एक महिला सशक्त होगी तो वह अपने पूरे परिवार का जीवन यापन सुचारू रूप से कर सकेंगी।

चौपाल निदेशक भोलानाथ विज ने कहा कि आज चौपाल संस्था ने अपने 80वें कार्यक्रम के दौरान 500 महिलाओं को दस–दस हज़ार का ऋण दिया। साथ ही 51 लोगों को ई–रिक्शा वितरित किए गए। चौपाल आज हजारों परिवारों तक पहुंच चुका है। इसका श्रेय उन स्वाभिमानी महिलाओं को ही जाता है जिन्होंने चौपाल द्वारा लिए गए ऋण को अपने समय अवधि के दौरान वापिस किया।

इस दौरान राजखुराना, सांसद मीनाक्षी लेखी, राजकुमार भाटिया, भारत भूषण मदन रवि बंसल, विनोद गोयल, तिलक राज कटारिया, रवि बंसल, प्रवीण बंसल, जय सिंह, रविंद्र इंद्रराज, मोहन भारद्वाज, विनोद गोयल, सौरभ नैय्यर, कुमार राजेश, बीना विरमानी, सुरेंद्र खर्ब समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ❑❑

https://punjabkesari.com/delhi-ncr/women-from-choupal-get-stronger-goyal/

डॉ.अश्वनी महाजन एवं श्री सुरेश प्रभु 'स्कॉच चैलेंजर अवार्ड' से सम्मानित

55वें स्कॉच समिट, द इकोनॉमिक मेनिफेस्टो द्वारा बीते 22 दिसंबर को आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ, ख्यातिलब्ध प्रोफेसर डॉ. अश्वनी महाजन को स्वदेशी अर्थशास्त्री के रूप में चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया।

अर्थतंत्र की बारीक समझ रखने वाले डॉ. महाजन ने देश के समक्ष खड़ी आर्थिक चुनौतियों से निपटने की न सिर्फ समझ विकसित की है, बल्कि तमाम मुद्दों पर उनके गहन चिंतन व अध्ययन के चलते कई एक प्रचलित आर्थिक नीतियों में बदलाव लाने का भी श्रेय उन्हें प्राप्त है। उनकी पुख्ता, प्रमाणिक और सफल नीतियों के हस्तक्षेप के कारण ही सरकार को भूमि अधिग्रहण पर विवादास्पद अध्यादेश वापिस लेना पड़ा था। इसी तरह जीएम फसलों की नीति का क्षेत्र परीक्षण करना, खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ई–कॉमर्स आदि के मामलों में भी इनके योगदान को स्वीकारा गया तथा सरकार ने इनकी सफल नीतियों को अपनी कार्यनीति का हिस्सा बनाया। विदेश व्यापार नीति के साथ–साथ डॉ. महाजन ने देश की सार्वजनिक नीति के मामलों पर भी सरकार का समय–समय पर उचित मार्गदर्शन किया है।

मालूम हो कि डब्ल्यूटीओ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर एक शोधकर्ता और कार्यकर्ता के रूप में डॉ. महाजन जिनेवा, बाली, नेरौबी, ब्यूनस आर्यस में आयोजित मंत्री स्तरीय सम्मेलनों में हिस्सा ले चुके है। ❑

वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु को भी 55वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में 'स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड' से सम्मानित किया गया। उनको यह सम्मान बिजली क्षेत्र में सुधारों के लिए दिया गया।

सुरेश प्रभाकर प्रभु एक सफल राजनीतिज्ञ हैं। वर्तमान में वे वाणिज्य और उद्योग एवं नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में भारत सरकार की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न संस्थानों द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणों में प्रदर्शन और पहुंच दोनों के संदर्भ में 2014 से 2017 तक लगातार भारत के शीर्ष पांच मंत्रियों की सूची में स्थान प्राप्त करते रहे हैं। श्री प्रभु को सरकार में जो भी जिम्मेवारी दी गई, उन्होंने उसका निर्वाह किया तथा एक सफल राजनेता की तरह योजनाओं को जमीन पर उतारने में अपनी सराहनीय भूमिका अदा की है। ❑

स्कॉच अवाड्र्स, भारतीय समाज में मानव उत्कृष्टता को प्रतिष्ठित करने और मनुष्य के जीवन में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए जुटे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार अनुकरणीय नेतृत्व क्षमताओं का प्रदर्शन करके समाज और शासन में सामयिक परिवर्तनों में बेहद योगदान देने वाले व्यक्तियों को पहचानने तथा सकारात्मक सामाजिक–आर्थिक बदलावों के दर्शन पर आधारित हैं। यह भारत में एक सर्वोच्च स्वतंत्र रूप से स्थापित नागरिक सम्मान हैं। वर्ष 2003 से इसकी शुरूआत की गई। स्कॉच अवाड्र्स शासन, वित्त, बैंकिंग, प्रौद्योगिकी, कॉर्पोरेट नागरिकता, अर्थशास्त्र और समावेशी विकास के क्षेत्र में भारत में एकमात्र स्वतंत्र बेंचमार्क बन गया है।

स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्रेरक नेतृत्व को प्रोत्साहित करता है। यह शासन, शिक्षा, परिवर्तन प्रबंधन, समावेशी विकास, नागरिक सेवाओं के वितरण, क्षमता निर्माण और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्रों में नेतृत्व में उत्कृष्टता दिखाने वालों के लिए स्थापित किया गया है। स्कॉच लाइफटाइम अचीवमेंट अवाड्र्स के लिए विश्वविद्यालयों, कॉलेजों को संभावित विजेताओं की पहचान के लिए ऐसे लोगों को नामित करने का परामर्श दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए मूलतः ऐसे व्यक्तियों को चुना जाता है जो किसी संस्था अथवा व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर उक्त क्षेत्रों में सराहनीय काम करते हो। ❑❑

स्वदेशी गतिविधियां

सचित्र झलकियां

स्वदेशी जागरण मंच और मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा 'शिक्षा और रोजगार क्षमता की खाई को भरने' विषय पर कार्यशला, मुंबई (14 दिसंबर 2018)

विचार गोष्ठी, मुजफ्फर नगर (उ.प्र.)

जिला सम्मेलन, करनाल (हरियाणा)

जिला सम्मेलन, पानीपत (हरियाणा)

जिला सम्मेलन, कुरूक्षेत्र (हरियाणा)

स्वदेशी पत्रिका
डाक तिथि 15–16 जनवरी 2019 नई दिल्ली पी.एस.ओ.
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/1/4074/2018-19-20
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

सचित्र झलकियां

स्वदेशी मिलन–समारोह, दिल्ली, 27 दिसंबर 2018 (श्री सरोज मित्र जन्मदिवस समारोह)

स्कॉच समिट 2018 में डॉ. अश्वनी महाजन को 'स्कॉच चैलेंजर अवार्ड' से सम्मानित किया गया।

स्वदेशी संगोष्ठी, आगरा (उ.प्र.)

जिला सम्मेलन, पानीपत (हरियाणा)

दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति व्याख्यानमाला, पटना (बिहार)

तुलसी पूजन दिवस, जयपुर (राज.)

प्रकाशक व मुद्रक ईश्वरदास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती